



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 16, 2018/चैत्र 26, 1940

No. 136]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 16, 2018/CHAITRA 26, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2018

(अंतिम जांच परिणाम)

विषय: चीन जनवादी गणराज्य, बेलारूस, उक्रेन, यूरोपीय संघ और पेरू के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एक्रिलिक फाइबर" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 14/50/-2016-डीजीएडी.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे अधिनियम भी कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित उसकी सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली (जिसे आगे यहां नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए मैसर्स इंडियन एक्रिलिक्स लि. और मैसर्स पशुपति एक्रिलन लि. (जिसे आगे यहां "याचिकाकर्ता" अथवा "घरेलू उद्योग" कहा गया है) ने चीन जन. गण., बेलारूस, उक्रेन, यूरोपीय संघ और पेरू (जिन्हें आगे यहां "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एक्रिलिक फाइबर (जिसे आगे यहां "संबद्ध सामान" कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू किए जाने के लिए अधिनियम एवं पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे यहां प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है और संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है।

2. जबकि, प्राधिकारी ने याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने के

लिए और पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 19 अप्रैल, 2017 की एक अधिसूचना द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी की जिसमें जो यदि लगाई जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिये पर्याप्त होगी।

क. प्रक्रिया

3. इस संबद्ध जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित निर्धारित प्रक्रिया अपनाई गई है:

i. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के उप नियम 5(5) के अनुसार, जांच की कार्यवाही की शुरुआत करने से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन पत्र प्राप्त होने के संबंध में भारत में स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।

ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित 19 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना जारी की।

iii. प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत की एक प्रति भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग तथा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार अन्य घरेलू उत्पादकों को भेजी और पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार जांच की शुरुआत की अधिसूचना के 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार देने का अनुरोध किया।

iv. प्राधिकारी ने ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलब्ध कराई।

v. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, जिनके ब्यौरे आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए थे, को संगत सूचना मंगाने के लिए निर्यातक प्रश्नावली भेजी:

- क) मोंटफाइबर स्पा, इटली (यूरोपीय संघ)
- ख) इंटरनेशनल रेयन एंड सिंथेटिक फाइबर्स कमेटी, बेल्जियम
- ग) एकोरडिस एजी, जर्मनी
- घ) ड्रेलोन जीएमबीएच, जर्मनी
- ङ) मरकिसचे फेसर एजी, जर्मनी
- च) इंटरनेशनल रेयन एंड सिंथेटिक फाइबर्स कमेटी, बेल्जियम
- छ) एकोरडिस यूके लि.
- ज) नेफ्टोखिम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, बुल्गारिया
- झ) लुकोइल कंपनी, बुल्गारिया
- ञ) जेएससी पॉलीमर, बेलारूस
- ट) अनकिंग पेट्रोकेमिकल, चीन जन. गण.
- ठ) पुमिका ट्रेडिंग कारपो. लि., लटविया
- ड) जिलिन किफेंग फाइबर कं. लि., चीन जन. गण.
- ढ) जिलिन जिमोंट एक्रिलिक फाइबर कं. लि., चीन जन. गण.
- ण) शंघाई पेट्रोकेमिकल, चीन जन. गण.
- त) किलु पेट्रोकेमिकल, चीन जन. गण.
- थ) सुबामेरिकाना डी फाइबर्स एस. ए., पेरू

vi. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे संबद्ध देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र एवं प्रश्नावली की प्रति उन्हें संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों एवं पतों के साथ भी भेजी गई।

vii. संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित प्रपत्र में निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए:

- क) सुबामेरिकाना डी फाइबर्स एस. ए. (उत्पादक) - पेरू
- ख) जिलिन किफेंग केमिकल फाइबर कं. लि. (उत्पादक/निर्यातक) - चीन जन. गण.
- ग) सिनोपेक शंघाई पैट्रोकेमिकल कं. लि. (उत्पादक) - चीन जन. गण.
- घ) चाइना जिनशान एसोसिएटेड ट्रेडिंग कारपोरेशन (निर्यातक) - चीन जन. गण.
- ङ) ड्रेलोन जीएमबीएच, जर्मनी (उत्पादक/निर्यातक) - यूरोपिय संघ
- च) ओपन ज्वाइंट-स्टॉक कंपनी नफ्टान (उत्पादक/निर्यातक) - बेलारूस

viii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं/ प्रयोक्ता एसोसिएशनों, जिनके नाम और पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे, को जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना की प्रति भेजी और उन्हें सलाह दी कि वे नियम 6(4) के अनुसार प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार दें:

- क) राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि., नई दिल्ली
- ख) वर्धमान स्पिनिंग एंड जनरल मिल्स, लुधियाना
- ग) दीपक स्पिनर्स लि., चंडीगढ़
- घ) मालवा कॉटन स्पिनिंग मिल्स लि., लुधियाना
- ङ) शिवालय स्पि. एंड वीवि. मिल्स (पी) लि., लुधियाना
- च) दीपक स्पिनर्स लि., सोलन बड़डू
- छ) शिवा फैब्रिकेटर (पी) लि., लुधियाना
- ज) सुप्रीम टेक्स मार्ट लि., लुधियाना
- झ) योगेंद्र वस्टेड लि., लुधियाना
- ञ) श्री राजस्थान सिंटेक्स लि., डूंगरपुर
- ट) बंसवाड़ा सिंटेक्स लि., बंसवाड़ा
- ठ) गंगा एक्रोवूल्स लि., लुधियाना
- ड) शीतल फाइबर्स लि., जालंधर
- ढ) अरिसुदाना इंडस्ट्रीज लि., लुधियाना
- ण) स्पोर्टकिंग इंडिया लि., लुधियाना
- त) टेक्सास वूलन मिल्स (पी) लि., लुधियाना
- थ) जिंदल कॉटेक्स लि., लुधियाना
- द) गर्ग एक्रिलिक्स लि., लुधियाना
- ध) इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन, मुंबई
- न) लुधियाना स्पिनर्स एसोसिएशन, लुधियाना

ix. उत्पाद के निम्नलिखित आयातकों अथवा उपभोक्ताओं ने निर्धारित प्रपत्र में आयातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए:

- क) गंगा स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि.
- ख) बंसवाड़ा सिंटेक्स लि., बंसवाड़ा
- ग) वनेक स्पिनिंग मिल्स लि.

x. जांच की अवधि के दौरान निम्नलिखित पक्षकारों ने अनुरोध/टिप्पणियां दायर कीं:

- 1. यूरोपीय संघ और भूटान के प्रतिनिधिमंडल,
- 2. बेलारूस गणराज्य का दूतावास, उक्रेन का दूतावास,
- 3. पेरू का दूतावास,
- 4. ट्रेलोन जीएमबीएच, जर्मनी;
- 5. चीन जन. गण. से जिलिन किफेंग केमिकल फाइबर कं. लि., सिनोपेक शंघाई पेट्रोकेमिकल कं. लि. और

चाइना जिनशान एसोसिएटेड ट्रेडिंग कारपोरेशन;

- 6. सुबामेरिकाना डि फाइबर्स एस. ए. (पेरू),
- 7. ओपन ज्वाइंट-स्टॉक कंपनी नफ्टान, बेलारूस,
- 8. इंडियन स्पिनर एसोसिएशन, पंजाब स्पिनर्स एसोसिएशन, सुप्रीम नोनवूवन इंडिया प्रा. लि., गंगा स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि., गंगा एक्रोवूल्स लि., बंसवाड़ा सिंटेक्स लि. और वनेक स्पिनिंग मिल्स लि.

xi. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले में रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराए। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर वर्तमान प्रकटन विवरण में ध्यान दिया गया है।

xii. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि अप्रैल, 2016 – मार्च, 2017 (12 माह) मानी गई है। क्षति जांच की अवधि अप्रैल, 2013 – मार्च, 2014, अप्रैल, 2014 – मार्च, 2015, अप्रैल, 2015 – मार्च, 2016 तथा जांच की अवधि मानी गई है।

xiii. आवेदक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक मानी गई सीमा तक अतिरिक्त/पूरक सूचना मांगी गई थी। घरेलू उद्योग एवं निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा दिए गए आंकड़ों का सत्यापन इस जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया।

xiv. क्षति रहित कीमत (एनआईपी) सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और उसे निर्मित करने तथा उसकी बिक्री करने की लागत पर आधारित है। यह इस तरह से निकाली गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

xv. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) द्वारा पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए लेन-देन वार आधार पर दी गई सूचना को भारत में संबंधित उत्पाद की मात्रा और आयात के मूल्य के निर्धारण के लिए अपनाया गया है।

xvi. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को संगत सूचना मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु 12 मार्च, 2018 को एक मौखिक सुनवाई की। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रकट किए, उन सभी को सलाह दी गई कि वे मौखिक रूप से प्रस्तुत अपने विचार लिखित

रूप में दायर करें। हितबद्ध पक्षकारों को विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के संबंध में अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया गया था।

xvii. जांच की अवधि के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध, जहां भी संगत पाए गए थे, प्राधिकारी द्वारा इस प्रकटन विवरण में हल कर लिए गए हैं।

xviii. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच उनके गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने, जहां भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय भाग उपलब्ध करायें।

xix. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने न तो प्राधिकारी को उत्तर दिया है और न ही वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना प्रस्तुत की है या जांच में काफी बाधा डाली है, उन्हें प्राधिकारी द्वारा असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना गया है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस प्रकटन विवरण में रिकार्ड किया गया है।

xx. प्राधिकारी ने 27 मार्च, 2018 को नियमावली के तहत प्रकटन विवरण जारी किया और 04 अप्रैल, 2018 तक प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां देने का अवसर प्रदान किया।

xxi. इस अंतिम जांच परिणाम में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से विचार किये जाने का द्योतक है।

xxii. जांच की अवधि के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनायी गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 67.95 रुपये है।

ख. विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु

4. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए विचाराधीन उत्पाद "एक्रिलिक फाइबर" (जिसे आगे संबद्ध सामान भी कहा गया है) है।

ख.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

5. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. एक्रिलिक फाइबर एक्रिलोनाइट्रिल यूनितों (उत्पादन के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री) के भार द्वारा कम से कम 90 प्रतिशत पर बनाए गए सिंथेटिक पॉलीमर की एक लंबी श्रृंखला है। एक्रिलिक फाइबर में एक्रिलिक स्टेपल फाइबर, एक्रिलिक टॉ तथा एक्रिलिक टॉप शामिल होते हैं जिन सबको वाणिज्यिक क्षेत्र में एक्रिलिक फाइबर के रूप में जाना जाता है। एक्रिलिक स्टेपल फाइबर और एक्रिलिक टॉ के बीच का अंतर केवल लंबाई का अंतर होता है। दो मीटर से अधिक की लंबाई के मामले में उसे टॉ के रूप में जाना जाता है और काटी गई लंबाई के मामले में उसे स्टेपल फाइबर के रूप में जाना जाता है। एक्रिलिक फाइबर के सभी रूप विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत हैं।

ख. एक्रिलिक फाइबर हल्का, मुलायम और गर्म होता है जो ऊन की तरह महसूस होता है। यह बहुत ही लचीला होता है और अन्य सिंथेटिक तथा प्राकृतिक फाइबर की तुलना में एसिड तथा अलकालीज में अत्यधिक प्रतिरोधकता दर्शाता है। एक्रिलिक फाइबर की कुछ किस्मों का प्रयोग सामग्री के समान अनुभव के कारण कश्मीरी ऊन के कम खर्चीले विकल्प के रूप में किया जाता है। एक्रिलिक फाइबर ऊन का एक किफायती प्रतिस्थापन है। एक्रिलिक फाइबर रंग अच्छे देता है, धुलाई योग्य है और सामान्यतः यह हाइपोएलर्जिक होता है।

ग. एक्रिलिक फाइबर 4 अंकों के स्तर पर उप शीर्ष 5501, 5503 और 5506 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 55 के अंतर्गत वर्गीकृत है। यह उत्पाद छः अंक के स्तर पर एचएस कोड 550130, 550330 और 550630 तथा आठ अंकों के स्तर पर 55013000 और 55033000 के अंतर्गत आता है।

घ. एकत्रिलिक फाइबर का अनुप्रयोग दैनिक मानव जीवन में होता है। एकत्रिलिक फाइबर के अनुप्रयोग एपैरल, घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों में कई तरह से होता है।

ङ. एकत्रिलिक फाइबर "मानव निर्मित स्टेपल फाइबर" की श्रेणी के अंतर्गत सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 55 में आता है।

च. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एकत्रिलिक फाइबर को पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, संबद्ध देशों से आयातित एकत्रिलिक फाइबर की समान वस्तु के रूप में माना जाना चाहिए।

ख.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

6. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. विचाराधीन उत्पाद को कम गुणवत्ता के ग्रेडों अथवा घटिया ग्रेडों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे तकनीकी विशेषताओं में कम गुणवत्ता के हैं और परिभाषा से विचाराधीन उत्पाद के रूप में वर्गीकृत किए जाने हेतु तकनीकी मानदंडों को पूरा नहीं करते।

ii. मैसर्स सुप्रीम नोनवोवन द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि होमो पॉलीमर एकत्रिलिक फाइबर उच्च गुणधर्मों वाला विशेष फाइबर होने के नाते उसे प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क से छूट दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत में होमो पॉलीमर एकत्रिलिक फाइबर का कोई उत्पादक नहीं है और यह कि इस उत्पाद को अगस्त, 2002 तथा 20 नवंबर, 2008 में जारी अधिसूचनाओं में पूर्व पाटनरोधी जांचों में अलग रखा गया था।

ख.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. विचाराधीन उत्पाद एकत्रिलिक फाइबर है। एकत्रिलिक फाइबर एकत्रिलोनाइट्रल यूनितों (उत्पादन के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री) के भार द्वारा कम से कम 90 प्रतिशत पर बनाए गए सिंथेटिक पॉलीमर की एक लंबी श्रृंखला है। एकत्रिलिक फाइबर में एकत्रिलिक स्टेपल फाइबर, एकत्रिलिक टॉ तथा एकत्रिलिक टॉप शामिल होते हैं जिन सबको वाणिज्यिक क्षेत्र में एकत्रिलिक फाइबर के रूप में जाना जाता है। एकत्रिलिक स्टेपल फाइबर और एकत्रिलिक टॉ के बीच का अंतर केवल लंबाई का अंतर होता है। दो मीटर से अधिक की लंबाई के मामले में उसे टॉ के रूप में जाना जाता है और काटी गई लंबाई के मामले में उसे स्टेपल फाइबर के रूप में जाना जाता है। एकत्रिलिक फाइबर के सभी रूप विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत हैं।

8. एकत्रिलिक फाइबर हल्का, मुलायम और गर्म होता है जो ऊन की तरह महसूस होता है। यह बहुत ही लचीला होता है और अन्य सिंथेटिक तथा प्राकृतिक फाइबर की तुलना में एसिड तथा अलकालीज में अत्यधिक प्रतिरोधकता दर्शाता है।

9. एकत्रिलिक फाइबर 4 अंकों के स्तर पर उन शीर्ष 5501, 5503 और 5506 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 55 के अंतर्गत वर्गीकृत है। यह उत्पाद एचएस कोड 550130, 550330 और 550630 के अंतर्गत आता है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और उत्पाद के क्षेत्र पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।

10. जहां तक कम गुणवत्ता अथवा दोयम ग्रेडों का मुद्दा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद को केवल गुणवत्ता के आधार पर जांच के क्षेत्र से अलग नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों ने इस बात का कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि निम्न गुणवत्ता वाले ग्रेड घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं। अतः, प्राधिकारी इन ग्रेडों को अलग न करने का निर्णय लेते हैं।

11. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि घरेलू उद्योग 100 प्रतिशत एकत्रिलोनाइट्रल से युक्त होमो पॉलीमर एकत्रिलिक फाइबर का निर्माण नहीं करता है। मैसर्स पशुपति एकत्रिलिन लि. से एक पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उन्होंने यह उल्लेख किया है कि वे होमो पॉलीमर एकत्रिलिक स्टेपल फाइबर का उत्पादन नहीं करते। अतः प्राधिकारी "100 प्रतिशत एकत्रिलोनाइट्रल से युक्त होमो पॉलीमर एकत्रिलिक फाइबर" को विचाराधीन उत्पाद क्षेत्र से अलग करने का निर्णय लेते हैं।

12. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करने के बाद प्राधिकारी मानते हैं कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध सामानों में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामान भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एक्रिलिक फाइबर आयातित एक्रिलिक फाइबर का तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है। प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है। तथापि, प्राधिकारी "100 प्रतिशत एक्रिलोनाइट्रिल से युक्त होमो पॉलीमर एक्रिलिक फाइबर" को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग करने का निर्णय लेते हैं।

ग. घरेलू उद्योग का कार्य क्षेत्र एवं स्थान

13. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"(ख) 'घरेलू उद्योग' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में 'घरेलू उद्योग' पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

ग.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

14. घरेलू उद्योग द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. यह याचिका मैसर्स इंडियन एक्रिलिक्स लि. और मैसर्स पशुपति एक्रिलिन लि. द्वारा दायर की गई है।

ख. भारत में संबद्ध सामानों का एक अन्य उत्पादक अर्थात् वर्धमान एक्रिलिक्स लि. है। वर्धमान एक्रिलिक्स लि. ने यूरोप से संबद्ध सामानों का काफी मात्रा में आयात किया है।

ग. याचिकाकर्ताओं का उत्पादन विचाराधीन उत्पाद के भारतीय उत्पादन का 78 प्रतिशत है।

घ. एक याचिकाकर्ता इंडियन एक्रिलिक्स लि. ने क्षति की अवधि के दौरान निर्यातों के विरुद्ध अग्रिम लाइसेंस के तहत थाइलैंड से संबद्ध सामानों का आयात किया है।

ङ. याचिकाकर्ता नियम 2(ख) के अभिप्राय से विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक अथवा आयातक से संबंधित (प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से) नहीं है।

च. यद्यपि, याचिकाकर्ता संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातक नहीं हैं, तथापि, वर्धमान एक्रिलिक्स लि. यूरोपीय संघ से विचाराधीन उत्पाद का नियमित आयातक है। वर्धमान एक्रिलिक्स लि. द्वारा किए गए आयात काफी हैं और वे उनकी अपनी खपत के लिए नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं का आधार है, चाहे वर्धमान एक्रिलिक्स को उसके आयातों के मद्देनजर घरेलू उद्योग का पात्र अथवा अपात्र घटक माना जाए।

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

15. इस संबंध में किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई अनुरोध नहीं किए हैं।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

16. वर्तमान आवेदन पत्र विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों के रूप में मैसर्स इंडियन एक्रिलिक्स लि. और मैसर्स पशुपति एक्रिलिन लि. द्वारा दायर किया गया है।

17. प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध सामानों के तीन मुख्य उत्पादकों में से दो हैं। याचिकाकर्ताओं का उत्पादन विचाराधीन उत्पाद के भारतीय उत्पादन का 78 प्रतिशत है।

18. उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनजर प्राधिकारी मानते हैं कि याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के संबंध में भारतीय घरेलू उद्योग हैं और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार की आवश्यकताएं पूरी करते हैं।

घ. गोपनीयता

घ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

19. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. यद्यपि, पेरू से एक उत्पादक ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं, तथापि, याचिकाकर्ता पेरूवियन उत्पादक द्वारा दावा की गई अत्यधिक गोपनीयता के मद्देनजर उस पर कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

20. इस संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. याचिकाकर्ताओं ने कैप्टिव एवं निर्यात बिक्री की मात्रा के संबंध में गोपनीयता का दावा करने में ट्रेड नोटिस संख्या 1/2009 के पैरा 2.ii के तहत अपेक्षित अच्छा कारणात्मक विवरण प्रदान नहीं किया है।

ख. याचिकाकर्ताओं ने ऐसा करने के लिए कोई आधार दिए बिना कैप्टिव एवं निर्यात बिक्री की मात्रा के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।

ग. यद्यपि, निर्यात एवं कैप्टिव बिक्री, दोनों की मात्रा मूल याचिका में उल्लिखित की गई है, तथापि, अद्यतन किए गए अनुमोदनों में उन्हें गोपनीय होने का दावा किया गया है। घरेलू उद्योग ने भी इन मानदंडों के विरुद्ध सूचीबद्ध आंकड़े प्रदान नहीं किए हैं और गोपनीयता के इस दुरुपयोग का सहारा लिया है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

21. पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में सूचना की गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान है:

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात को होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

22. घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने, जहां भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया गया है।

ड. विविध मुद्दे**ड.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

23. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

क. एक से अधिक देश से निर्यातक भारतीय बाजार में संबद्ध सामानों का पाटन कर रहे हैं। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II(iii) के तहत प्रावधानों के अनुसार यदि एक से अधिक देश से उत्पाद के आयात पाटनरोधी जांचों में साथ-साथ रखे जा रहे हैं तो प्राधिकारी को ऐसे आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन संचयी रूप से करना चाहिए।

ख. संबद्ध देशों से निर्यात कीमत ग्राहक एवं समयावधि के संदर्भ में काफी भिन्न है और इसीलिए यह एक उपयुक्त मामला है जहां भारित औसत सामान्य मूल्य की तुलना भारित औसत निर्यात कीमत से नहीं की जा सकती। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे भारित औसत सामान्य मूल्य पर विचार करें और अलग-अलग निर्यात कीमत से तुलना करें तथा उन सभी आयात लेन-देनों में, जहां पाटन मार्जिन नकारात्मक है, उसे पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए अलग रखा जाए।

ग. उक्रेनाई आयातों को जांच के क्षेत्र से अलग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक सुनिर्धारित कानून है कि क्षति विश्लेषण, जांच की अवधि को मानते हुए किया जाता है। पिछले वर्षों को केवल तुलनात्मक विश्लेषण करने के लिए ही ध्यान में रखा जाता है।

घ. शुल्क तभी लगाए जाने होते हैं जब पाटन के क्रियाकलापों के उदाहरण हों। किसी हितबद्ध पक्षकार ने यह सिद्ध नहीं किया है कि शुल्क लगाने से कैसे निचले प्रयोक्ताओं पर प्रभाव पड़ेगा।

ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

24. इस संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

क. बेलारूस से आयात याचिकाकर्ता के अनुसार जांच की अवधि के दौरान भारत में कुल आयातों का केवल 2.94 प्रतिशत था। इसे याचिका में कुल मिलाकर कई जगह 3 प्रतिशत दर्शाया गया है। बेलारूस के विरुद्ध जांच कानूनी तौर पर बुरी है और उसे तत्काल रद्द किया जाना चाहिए।

ख. ताइवान को वर्तमान जांच के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। यह भेद-भाव पूर्ण है और इससे क्षति का पूरा कारणात्मक संपर्क विश्लेषण दुष्प्रभावित भी होता है। इस स्थिति से भी नियम 5(3) के मद्देनजर वर्तमान जांच को रद्द किए जाने की आवश्यकता है।

ग. घरेलू उद्योग द्वारा उनकी याचिका में प्रस्तुत की गई पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता के संबंध में दिए गए आंकड़े उनकी वार्षिक रिपोर्ट से भिन्न हैं तथा उन आंकड़ों के विपरीत हैं।

घ. भारत में आयातित संबद्ध सामानों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्द्धा की स्थितियां और भारत में आयातित संबद्ध सामानों के बीच प्रतिस्पर्द्धा की स्थितियां तथा समान घरेलू उत्पाद के बीच स्थितियां समान नहीं हैं। अतः संचयी मूल्यांकन उपयुक्त नहीं होगा।

ड. संचयी मूल्यांकन करने के लिए प्राधिकारी के लिए अपेक्षा इस तथ्य पर विकृत है कि ताइवान को संबद्ध देशों के क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है और बेलारूस का हिस्सा जांच की शुरुआत के समय कुल आयात में 3 प्रतिशत से कम था। ऐसी स्थिति होने पर कोई भी संचयी मूल्यांकन करने से विकृत निष्कर्ष निकलेंगे और ताइवान सहित देश-वार जांच वर्तमान मामले में की जानी चाहिए।

च. अंतिम प्रयोक्ता उद्योग पहले ही पाटन के दबाव में चल रहा है और घरेलू उद्योग द्वारा पेश की गई कीमतें प्रतिस्पर्द्धा नहीं हैं। इन अंतिम प्रयोक्ताओं के हित में घरेलू उद्योग को कोई पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे विचाराधीन उत्पाद के भारी संख्या में छोटे पैमाने के प्रयोक्ता बंद हो जाएंगे।

छ. यूरोपीय संघ से आयातों को आयातों के प्रभाव के संचयी मूल्यांकन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यूरोपीय संघ से विचाराधीन उत्पाद का पहुँच मूल्य उच्चतम है, यूरोपीय संघ से आयातों के बाजार हिस्से में जांच की अवधि में गिरावट आई है और यूरोपीय संघ से आयातों की मात्रा में जांच की अवधि में गिरावट आई है।

ज. सन् 1996 से शुरू की गई लगभग प्रत्येक पाटनरोधी जांच में पाटनरोधी शुल्कों की सिफारिश की गई है और एक्रिलिक फाइबर के आयातों पर शुल्क लगाए गए हैं, जिनमें से कुछ अब भी लगे हुए हैं। इस प्रकार, एक्रिलिक फाइबर के घरेलू उत्पादकों को पाटनरोधी शुल्कों द्वारा आयातों से पर्याप्त संरक्षण से अधिक संरक्षण प्राप्त है।

झ. इस संदर्भ में कि काफी विशिष्ट ग्रेड का आयात किया गया है, पाटन एवं क्षति मार्जिन के निर्धारण में उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए पीसीएन-वार तुलना की जाए। उत्पाद में यहां विविध प्रकार के ग्रेड और किस्में शामिल हैं और सबसे अच्छा तरीका यही है कि पीसीएन विश्लेषण किया जाए।

इ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

25. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों के संबंध में प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

क. बेलारूस से आयातों के मुद्दे के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान बेलारूस से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की वास्तविक मात्रा विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों की मात्रा के 3 प्रतिशत से अधिक है। अतः इस अनुरोध में कोई औचित्य नहीं है कि बेलारूस के विरुद्ध जांच पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रद्द की जाए।

ख. जांच के क्षेत्र में ताइवान को शामिल करने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह दर्शाने के लिए कोई तर्क नहीं दिया गया है या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि ताइवान से विचाराधीन उत्पाद के आयातों का भारत में पाटन हो रहा है। अतः इस जांच के क्षेत्र में ताइवान को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।

च. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी), सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

सामान्य मूल्य

26. सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

च.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

27. घरेलू उद्योग द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. चीन जन. गण. अभिगम नवाचार का एक प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गया है। निर्दिष्ट अधिकारी चीनी उत्पादकों को निम्नलिखित कारणों से गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में प्रचालन करने वाले उत्पादकों के रूप में मान सकते हैं।

i. वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित जांच की अवधि जुलाई, 2016 से दिसंबर, 2016 (6 माह) है। क्षति की जांच की अवधि 2013-14, 2014-15, 2015-16, अप्रैल-जून, 2016 तथा जांच की अवधि प्रस्तावित की गई है।

ii. चीनी उत्पादकों को इन कारणों से गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली कंपनियां माने जाने की आवश्यकता है कि चीन में लागतें एवं कीमतें बाजार बलों में उपयुक्त रूप से नहीं दर्शाई जाती हैं।

iii. चीनी उत्पादकों को तब तक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली कंपनियां माने जाने की आवश्यकता है जब तक जांच की अवधि में चीनी अभिगम नवाचार में विनिर्दिष्ट अवधि शामिल न हो जाए।

ख. चीन जन. गण. में अभिगम नवाचार के अनुसार, 11 दिसंबर, 2016 तक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माने जाने के लिए सहमति दे दी थी। तकनीकी रूप से वर्तमान जांच में चीन जन. गण. में प्रस्तावित क्षति की अवधि तथा जांच की अवधि के दौरान एनएमई स्तर माना। अतः इस जांच में चीन जन. गण. के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

ग. चीन जन. गण., बेलारूस और उक्रेन में सामान्य मूल्य – चूंकि वे गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, अतः प्राधिकारी को चाहिए कि वे पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 को अपनाएं।

घ. उक्रेन और बेलारूस से किसी भी निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। इस प्रकार, इन देशों का सामान्य मूल्य याचिकाकर्ताओं द्वारा लिखित अनुरोधों तथा सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

ङ. याचिकाकर्ताओं ने सीएफआर आधार पर प्रस्तावित जांच की अवधि के लिए आईएचएस केमिकल रिपोर्टों के अनुसार एशिया (सुदूरपूर्व) क्षेत्र में विद्यमान एक्रिलिक फाइबर की क्षेत्रीय कीमतों के आधार पर चीन जन. गण., बेलारूस और उक्रेन ने सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा किया है। प्राधिकारी कृपया इन कीमतों पर व्यापार परीक्षण की सामान्य अवधि लागू करें और यह सुनिश्चित करें कि ये कीमतें पूर्ण उत्पादन लागत से अधिक हैं।

च. याचिकाकर्ता आईएचएस केमिकल रिपोर्टों के अनुसार, पश्चिमी यूरोप क्षेत्र में विद्यमान सुपुर्दगी आधार कीमतों का साक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम रहे हैं और उन्होंने इन कीमतों को प्रस्तावित जांच की अवधि के लिए सामान्य मूल्य के लिए आधार के रूप में अपनाया है। प्राधिकारी कृपया इन कीमतों पर व्यापार परीक्षण की सामान्य अवधि लागू करें और यह सुनिश्चित करें कि ये कीमतें पूर्ण उत्पादन लागत से अधिक हैं।

छ. याचिकाकर्ता आईएचएस केमिकल रिपोर्टों के अनुसार, दक्षिण अमेरिका क्षेत्र में विद्यमान सुपुर्दगी आधार कीमतों का साक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम रहे हैं और उन्होंने इन कीमतों को प्रस्तावित जांच की अवधि के लिए सामान्य मूल्य के लिए आधार के रूप में अपनाया है। प्राधिकारी कृपया इन कीमतों पर व्यापार परीक्षण की सामान्य अवधि लागू करें और यह सुनिश्चित करें कि ये कीमतें पूर्ण उत्पादन लागत से अधिक हैं।

ज. वे सभी आयात लेन-देन जहां पाटन मार्जिन नकारात्मक है, पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए अलग किए जाने चाहिए।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

28. सामान्य मूल्य के संबंध में विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

क. प्राधिकारी को निर्यातकों द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का परिकलन कर पाटन मार्जिन निर्धारित करना चाहिए।

ख. उक्रेन को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए। भारत ने पहले ही कोल्ड रोलड काइल की जांच में उक्रेन को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश में माना है।

ग. ओजेएससी नाफ्टान द्वारा एक्रिलिक फाइबर की निर्यात कीमतें जांच की अवधि में बेलारूस में एक्रिलिक फाइबर की घरेलू बिक्री कीमतों से अधिक हैं।

घ. बेलारूस गणराज्य बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत सरकार ने 2015 में राष्ट्रपति मुखर्जी की बेलारूस यात्रा के दौरान बेलारूस को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना।

ङ. उन लेन-देनों को, जहां पाटन मार्जिन नकारात्मक है, अलग करना शून्यकरण के रूप में ज्ञात सिद्धांत है जिसे निष्कर्ष स्वरूप असंगत एवं पाटनरोधी करार और पाटनरोधी नियमावली के उल्लंघन में माना गया है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

29. संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली दायर की है:

- क) सुबामेरिकाना डी फाइबर्स एस. ए. (उत्पादक) - पेरू
- ख) जिलिन किफेंग केमिकल फाइबर कं. लि. (उत्पादक/निर्यातक) - चीन जन. गण.
- ग) सिनोपेक शंघाई पेट्रोकेमिकल कं. लि. (उत्पादक) - चीन जन. गण.
- घ) चाइना जिनशान एसोसिएटेड ट्रेडिंग कारपोरेशन (निर्यातक) - चीन जन. गण.
- ङ) ड्रेलोन जीएमबीएच, जर्मनी (उत्पादक/निर्यातक) - यूरोपिय संघ
- च) ओपन ज्वाइंट-स्टॉक कंपनी नफ्टान, बेलारूस

क) बाजार अर्थव्यवस्था दावों और सामान्य मूल्य की जांच

30. चाइनीज एसेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

(क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन

और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

31. अनुच्छेद 15 का अभिप्राय है कि एक उप पैरा के प्रावधान चीनी अभिगम की तारीख से 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इस उप पैरा के प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गए। चूंकि, घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाले पाटन का तथ्य जांच की अवधि के आधार पर सिद्ध है, अतः जांच की अवधि के दौरान विद्यमान स्थितियां ही संगत, उपयुक्त और वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं। वर्तमान समीक्षा के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 है। चूंकि, अनुच्छेद 15 का उप पैरा जांच की अधिकतर अवधि के दौरान मौजूद था, अतः प्राधिकारी उस सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं जो चीन में घरेलू लागतों अथवा कीमतों की शक्ति से तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांच के अधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह न दर्शा सकें कि विनिर्माण, उत्पादन और उस उत्पाद की बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं।

32. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पिछले तीन वर्षों में भारत तथा अन्य डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा पाटनरोधी जांचों में चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है। चीन जन. गण. को नियमावली के अनुसार निर्यातक देश अथवा अलग-अलग निर्यातकों द्वारा अवधारणा के खंडन के अध्यधीन गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है।

33. यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली के पैरा-8, अनुबंध-1 के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का उस स्थिति में खंडन किया जा सकता है यदि चीन जन. गण. का निर्यातक पैरा 8 के उप पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करता है। चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार संबंधी प्रस्तावली के उत्तर में पैरा 8 के उप पैरा (3) में किए गए उल्लेख के अनुसार आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करना अपेक्षित है ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित मानदंडों पर विचार कर सकें कि क्या:-

क. कच्ची सामग्रियों सहित कीमत; लागत और निविष्टि तथा श्रम लागत, उत्पादन, बिक्रियां और निवेश के बारे में चीन जन. गण. में संबंधित फर्मों का निर्णय ऐसे बाजारी संकेतों के अनुसार किया जाता है जिसमें आपूर्ति और मांग परिलक्षित होती है और इस बारे में राज्य का अधिक हस्तक्षेप नहीं होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजार मूल्य पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होता है;

ख. इस प्रकार की फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति विशेषकर परिसंपत्तियों के मूल्यहास, अन्य बट्टे-खातों, वस्तु विनिमय-व्यापार और ऋणों की प्रतिपूर्ति के माध्यम से भुगतान के संदर्भ में पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली प्रणाली से हुई महत्वपूर्ण विकृतियों के अध्यधीन है;

ग. इस प्रकार की फर्मों दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अध्यधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं;

घ. विनिमय दर का परिवर्तन बाजार दर पर किया जाता है।

चीन जन. गण. में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

34. चीन जन. गण. से किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था के स्तर का दावा नहीं किया है। किसी भी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश ने संबद्ध सामानों के लिए विश्वसनीय कीमत/लागत के ब्यौरों के अभाव में चीन के लिए सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग के सर्वाधिक दक्ष घटक के खपत मानदंडों तथा अधिकतम लागत और उपयुक्त लाभ पर विचार करते हुए निर्मित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में यहां नीचे दिया गया है।

बेलारूस में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

35. बेलारूस से सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य संबंधित उत्पादक/ निर्यातक द्वारा दी गई सूचना के आधार पर निर्धारित किया गया है क्योंकि बेलारूस को भारत सरकार द्वारा एक बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है जो कि वाणिज्यिक विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से दिनांक 10.06.2015 के पत्र संख्या 11/1/2013-एफटी (सीआईएस) द्वारा बेलारूस गणराज्य के दूतावास को सूचित किया गया था।

ओपन ज्वाइंट-स्टॉक कंपनी नाफ्टान (बेलारूस)

36. बेलारूस ने उत्पादकों/निर्यातकों से प्रश्नावली के उत्तरों के मद्देनजर उत्तरदाता उत्पादकों एवं निर्यातकों के मामले में सामान्य मूल्य तथा पाटन मार्जिन, उनकी प्रश्नावली के उत्तरों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

37. निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर से प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैसर्स नाफ्टान संबद्ध सामानों का उत्पादक/निर्यातक है। निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में उपलब्ध सूचना के अनुसार, जांच की अवधि के दौरान नाफ्टान ने असंबद्ध ग्राहकों को *** मी. टन घरेलू बिक्री की। बिक्री पर किए गए व्यापार (80:20) परीक्षण की सामान्य अवधि यह दर्शाती है कि *** प्रतिशत बिक्री लाभप्रद थी। अतः जांच की अवधि में संबद्ध सामानों का सामान्य मूल्य संबद्ध देश में लाभप्रद घरेलू बिक्री की औसत कीमत को लेकर निर्धारित किया गया है। कंपनी द्वारा सामान्य मूल्य से किसी समायोजन का दावा नहीं किया गया है। इस प्रकार, माना गया सामान्य मूल्य *** अमेरिकी डॉलर/मी. टन है।

यूक्रेन में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

38. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूक्रेन से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। यूक्रेन में सभी उत्पादक-निर्यातकों से असहयोग के मद्देनजर प्राधिकारी ने नियम 6(8) के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है और उसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

यूरोपीय संघ से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

ड्रेलोन जीएमबीएच, जर्मनी (निर्यातक/उत्पादक)

39. निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर से प्राधिकारी नोट करते हैं कि ड्रेलोन जीएमबीएच संबद्ध सामानों का उत्पादक और निर्यातक है। ड्रेलोन ने घरेलू बाजार में की गई बिक्री के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। निर्यातक प्रश्नावली में उपलब्ध सूचना के अनुसार जांच की अवधि में ड्रेलोन ने असंबद्ध ग्राहकों को *** मी. टन घरेलू बिक्री की। ड्रेलोन की बिक्री पर किए गए व्यापार (80:20) परीक्षण की सामान्य अवधि यह दर्शाती है कि *** प्रतिशत बिक्री लाभप्रद थी। अतः जांच की अवधि में संबद्ध सामानों का सामान्य मूल्य संबद्ध देश में लाभप्रद घरेलू बिक्री की औसत कीमत को लेकर निर्धारित किया गया है। ड्रेलोन ने अंतर्देशीय भाड़ा, पैकिंग लागत, कमीशन और ऋण लागत के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने उचित सत्यापन के बाद उसकी अनुमति दी है और इस प्रकार, सामान्य मूल्य *** अमेरिकी डॉलर/मी. टन के रूप में निकाला है।

पेरू में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

सुबामेरिकाना डि फाइबर्स, एस. ए., पेरू (उत्पादक)

40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पेरू से सुबामेरिकाना डि फाइबर्स एस. ए. ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं।

41. निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर से प्राधिकारी नोट करते हैं कि सुबामेरिकाना डि फाइबर्स, पेरू संबद्ध सामानों का उत्पादक है। सुबामेरिकाना डि फाइबर्स ने घरेलू बाजार में की गई बिक्री के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। तथापि, बाद के पैराग्राफ में दिए गए कारणों से सुबामेरिकाना डि फाइबर्स एस. ए. के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्मित किया गया है।

यूरोपीय संघ, बेलारूस और पेरू से असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

42. यूरोपीय संघ, बेलारूस और पेरू के अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर माना गया है। इस आधार पर पाटन मार्जिन, पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ख) निर्यात कीमत

चीन जन. गण. से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

43. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं:

- क) जिलिन किफेंग केमिकल फाइबर कं. लि. (उत्पादक/निर्यातक) – चीन जन. गण.
- ख) सिनोपेक शंघाई पेट्रोकेमिकल कं. लि. (उत्पादक) – चीन जन. गण.
- ग) जिनशान एसोसिएटेड ट्रेडिंग कारपोरेशन (निर्यातक) – चीन जन. गण.

44. चीन जन. गण. ने उत्पादकों/निर्यातकों से प्रश्नावली के उत्तर के मद्देनजर उत्तरदाता उत्पादकों और निर्यातकों के मामले में निर्यात कीमत उनके प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर निर्धारित की गई है।

मैसर्स जिलिन किफेंग केमिकल फाइबर कं. लि. ("जिलिन") (उत्पादक/निर्यातक), चीन जन. गण.

45. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जिलिन ने भारत को संबद्ध सामान के *** मी. टन का निर्यात किया है। भारत को सभी निर्यात असंबद्ध भारतीय ग्राहकों को सीधे ही किए गए थे। जिलिन ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय भाड़ा और पत्तन सार संभाल प्रभारों के निमित्त समायोजनों का दावा किया था। प्राधिकारी ने कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए बैंक प्रभारों और ऋण लागत के लिए समायोजन किए थे। जिलिन के लिए कारखानागत निर्यात कीमत *** अमेरिकी डॉलर/मी. टन के रूप में निर्धारित की गई है।

मैसर्स सिनोपेक शंघाई पेट्रोकेमिकल कं. लि. ("सिनोपेक") (उत्पादक) और मैसर्स जिनशान एसोसिएटेड ट्रेडिंग कारपोरेशन (जिनशान) (निर्यातक), चीन जन. गण.

46. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सिनोपेक ने भारत को सीधे ही तथा संबंधित व्यापारी जिनशान के माध्यम से संबद्ध सामानों के *** मी. टन का निर्यात किया है। संबंधित व्यापारी ने हांगकांग में स्थित दूसरे व्यापारी जिन्हें ट्रेडिंग एचके लिमिटेड के माध्यम *** मी. टन का निर्यात किया है। जिन्हें ट्रेडिंग एचके लिमिटेड ने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है। तदनुसार, प्राधिकारी सिनोपेक और जिनशान द्वारा दायर उत्तर को स्वीकार न करने का निर्णय लेते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी ने नियम 6(8) के अनुसार, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है और वह नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

बेलारूस से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

ओपन ज्वाइंट-स्टॉक कंपनी नाफ्टान (बेलारूस)

47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नाफ्टान ने भारत में असंबद्ध ग्राहकों को भारत को संबद्ध सामानों के *** मी. टन का निर्यात किया है। नाफ्टान ने निर्यात कीमत से किसी समायोजन का दावा नहीं किया है। भारत को सभी निर्यात बिक्री एफसीए आधार पर थी। अतः प्राधिकारी ने कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए अंतर्देशीय भाड़ा, पत्तन सार संभाल प्रभार, बैंक प्रभार और ऋण लागत के निमित्त उचित समायोजन किए हैं। कारखानागत निर्यात कीमत *** अमेरिकी डॉलर/ मी. टन के रूप में निर्धारित की गई है।

यूरोपीय संघ से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण**ड्रेलोन जीएमबीएच (उत्पादक/निर्यातक)**

48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ड्रेलोन जीएमबीएच ने भारत में असंबद्ध ग्राहकों को संबद्ध सामानों के *** मी. टन का निर्यात किया है। ड्रेलोन ने कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय भाड़ा, पत्तन सार संभाल प्रभार, कमीशन और ऋण लागत के निमित्त समायोजनों का दावा किया है और प्राधिकारी ने उचित सत्यापन के बाद उसकी अनुमति दी है। कारखानागत निर्यात कीमत *** अमेरिकी डॉलर/मी. टन के रूप में निर्धारित की गई है।

यूक्रेन से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

49. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूक्रेन से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। यूक्रेन में सभी उत्पादक-निर्यातकों से असहयोग के मद्देनजर प्राधिकारी ने नियम 6(8) के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है और वह नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

पेरू से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण**सुबामेरिकाना डि फाइबर्स एस. ए., पेरू (उत्पादक)**

50. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सुबामेरिकाना डि फाइबर्स ने भारत को संबद्ध सामानों के *** मी. टन की बिक्री की है। उत्पादक द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि भारत को सभी निर्यात सीधे ही भारतीय ग्राहकों को किए गए थे। उत्पादक द्वारा दायर उत्तर से प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को लगभग *** प्रतिशत निर्यात दुबई आधारित व्यापारियों अर्थात् मैसर्स ट्रांस गेलेक्टिक ट्रेडिंग एफजेड और मैसर्स लानास फाइबर्स लिमिटेड के माध्यम से किए गए थे। इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा दिए गए नमूना दस्तावेजों से यह अनुरोध किया जाता है कि उत्पादक द्वारा सूचित की गई निर्यात कीमत निर्यात बीजकों में मूल्यों से मेल नहीं खाती है। अतः प्राधिकारी सुबामेरिकाना डि फाइबर्स के उत्तर को स्वीकार न करने का निर्णय लेते हैं। तदनुसार, सुबामेरिकाना डि फाइबर्स के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है।

चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, बेलारूस और पेरू से असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

51. चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, बेलारूस और पेरू के अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मानी गई है। इस आधार पर पाटन मार्जिन, पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

च.4 पाटन मार्जिन का परिकलन

52. निर्धारित किए गए उपर्युक्त सामान्य मूल्य और निर्यात कीमतों की तुलना करते हुए जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन निम्नलिखित है:

पाटन मार्जिन तालिका

देश	उत्पादक	निर्यातक	सामान्य मूल्य अमेरिकी डॉलर/मी. टन	कारखानागत निर्यात कीमत अमेरिकी डॉलर/मी. टन	पाटन मार्जिन अमेरिकी डॉलर/मी. टन	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेंज
चीन जन. गण.	मैसर्स जिलिन किफेंग केमिकल फाइबर कं. लि.	मैसर्स जिलिन किफेंग केमिकल फाइबर कं. लि.	***	***	***	***	0-10
चीन जन. गण.	अन्य सभी	अन्य सभी	***	***	***	***	0-10
बेलारूस	ओपन ज्वाइंट –	ओपन ज्वाइंट –	***	***	***	***	30-40

देश	उत्पादक	निर्यातक	सामान्य मूल्य	कारखागत निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
	स्टॉक कंपनी नफटान	स्टॉक कंपनी नफटान					
बेलारूस	अन्य सभी	अन्य सभी	***	***	***	***	65-75
यूरोपीय संघ	ड्रेलोन जीएमबीएच	ड्रेलोन जीएमबीएच	***	***	***	***	10-20
यूरोपीय संघ	अन्य सभी	अन्य सभी	***	***	***	***	30-40
उक्रेन	सभी	सभी	***	***	***	***	0-10
पेरू	सभी	सभी	***	***	***	***	20-30

53. यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से प्रत्येक सहयोगी उत्पादक/निर्यातक तथा असहयोगी उत्पादक/निर्यातक से किए गए निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिन नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक है।

छ. क्षति का निर्धारण और कारणात्मक संबंध

54. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण भारत में घरेलू समान उत्पाद को वास्तविक क्षति हो रही है। यह निर्धारित करने पर कि सामान पाटित कीमतों पर संबद्ध देशों से आ रहे हैं, प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हुई क्षति, यदि कोई है, की मात्रा और सीमा की जांच करने के लिए कार्रवाई करते हैं।

55. अनुबंध-11 के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ... "ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक हो गई होती।"

छ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

56. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- संबद्ध सामानों की पहुँच कीमत बिक्री की लागत तथा बिक्री कीमत से कम रही है। आयातों से घरेलू कीमतों का न्यूनीकरण/हास हो रहा है।
- आयातों के परिणामस्वरूप काफी कम कीमत पर बिक्री हो रही है, जैसा कि क्षति रहित कीमत और आयातों की पहुँच कीमत के बीच अंतर द्वारा सिद्ध है।
- घरेलू उद्योग के निष्पादन में उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री, मालसूची, लाभ, निवेश पर आय, नकद प्रवाह और बाजार हिस्से की दृष्टि से हास हुआ है।
- घरेलू उद्योग के निष्पादन में हास तिमाही आधार पर जांच की अवधि में अधिक प्रमुख है।
- घरेलू उद्योग मौजूदा एवं नए स्रोतों से बाजार में सतत पाटित आयातों के कारण पूरी सीमा तक अपनी क्षमताओं का उपयोग करने से रुक गया है।
- घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा क्षति की अवधि में बहुत ज्यादा कम हुआ है, जबकि संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। भारतीय उद्योग का बाजार हिस्सा समग्र रूप से मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद कम हुआ है।
- घरेलू उद्योग कोई भी नया निवेश करने की स्थिति में नहीं है।

- viii. घरेलू उद्योग के निष्पादन के और अधिक ह्रास को रोकने के लिए संबद्ध देशों पर तत्काल पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है।
- ix. किसी भी उद्योग का क्षमता उपयोग समग्र रूप से उत्पादों के लिए देखा जाता है क्योंकि उत्पादों के स्तर पर घरेलू एवं निर्यात उत्पादों को अलग-अलग नहीं किया जा सकता।
- x. रोजगार एवं मजदूरी घरेलू उद्योग को हो रही क्षति को सही दर्शाने वाले कारक नहीं हैं।
- xi. लगाई गई पूंजी पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग ने वर्तमान मामले में मात्रात्मक क्षति का दावा किया है।
- xii. पाटन मार्जिन सकारात्मक है और इसीलिए यह तथ्य कि आयात कीमतों में कच्ची सामग्री की कीमत में गिरावट के कारण गिरावट आई है, असंगत है। घरेलू उद्योग पर कीमत कटौती तथा आयात में परिणामस्वरूप वृद्धि के कारण प्रतिकूल मात्रात्मक प्रभाव पड़ा है। प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में उत्पादन, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सा, बिक्री की मात्रा में गिरावट आई है और मालसूची में वृद्धि हुई है।
- xiii. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की निवेश पर आय काफी कम रही है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की उसकी शुरुआत से ही निवेश पर औसत आय काफी कम रही है। घरेलू उद्योग ने शेयरधारकों को कभी लाभांश नहीं दिया है और वह काफी कम क्रेडिट रेटिंग का सामना कर रहा है।
- xiv. कीमत कटौती का निर्धारण केवल क्षतिकारक आयात लेन-देनों पर विचार कर ही किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की चिंता क्षति रहित आयातों के विरुद्ध नहीं है। कोठारी शुगर्स एंड केमिकल लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में माननीय सेसटेट के निर्णय का संदर्भ दिया जाता है। यूरोपीय आयोग – ट्यूव अथवा पाइप फिटिंग में डब्ल्यूटीओ पैनेल रिपोर्ट का भी संदर्भ दिया जाता है।

छ.2 विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

57. इस संबंध में विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. घरेलू उद्योग के क्षति के दावों की प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त जांच किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि तथ्य कठोर स्थिति दर्शाते हैं।
- ii. मांग तदनुसारी नहीं गिरी है। निर्यातक भारतीय प्रयोक्ताओं की विविध आवश्यकताओं को देखते हुए विशेष उत्पाद की आपूर्ति करने में सक्षम हैं और घरेलू उद्योग की विशेष ग्रेडों की मांग को पूरा करने में असमर्थता को बाजार हिस्से के लिए प्रतिकूल प्रभाव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
- iii. घरेलू बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट नहीं आई है बल्कि वह काफी बढ़ी है। वस्तुतः 2015-16 और 2016-17 में घरेलू उद्योग ने बड़े लाभ कमाए हैं। इसी प्रकार, क्षति की अवधि में नकद लाभ, ब्याज एवं कर पूर्व लाभ तथा पूंजी पर आय में काफी वृद्धि हुई है।
- iv. क्षति की अवधि में उत्पादन एवं क्षमता उपयोग में काफी वृद्धि हुई है। वस्तुतः जांच की अवधि में क्षमता उपयोग 89 प्रतिशत की ऊंचाई पर रहा है।
- v. घरेलू बिक्री में गिरावट आई है क्योंकि घरेलू उद्योग अपना उत्पादन निर्यात बिक्री के लिए ले जा रहा है जो कि निर्यात बिक्री मूल्य में वृद्धि से देखा जा सकता है।
- vi. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री मात्रा में गिरावट को भारत में संबद्ध सामानों के लिए कुल मांग में गिरावट द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।
- vii. पशुपति एक्जिलन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट खुद ही बताती है कि उसने निर्यात पर जोर बढ़ाने के लिए सजग निर्णय लिया है।
- viii. भारत में याचिकाकर्ताओं के बाजार हिस्से में निर्यात पर बढ़े हुए जोर और घरेलू बाजार में मांग में गिरावट के कारण

गिरावट आई है।

- ix. अन्य घरेलू उत्पादक – वर्धमान एक्रिलिक्स लि. का बाजार हिस्सा कुल मिलाकर संबद्ध देशों से आयात मात्रा में पूर्ण वृद्धि के बावजूद समान रहा है। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग अन्य घरेलू उत्पादक की तरह दक्ष एवं प्रतिस्पर्द्धी नहीं रहा है।
- x. यूरोपीय संघ से आयातों के बाजार हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई है।
- xi. घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि निर्यात बिक्री में वृद्धि के कारण है। मालसूची में वृद्धि का मूल्यांकन कुल बिक्री मात्रा की प्रतिशतता के रूप में ही किया जाना चाहिए।
- xii. उत्पादन और खपत, दोनों के अनुपात के रूप में आयात मात्रा में वृद्धि पूरी क्षति की अवधि में 10 प्रतिशत से अधिक नहीं रही है जिसे काफी माना जा सकता है।
- xiii. समग्र आयातों के अनुपात के रूप में संबद्ध आयातों का हिस्सा मात्रात्मक प्रभाव और फिर क्षति के निर्धारण के लिए कारक नहीं है।
- xiv. यूरोपीय संघ से आयातों की मात्रा में जांच की अवधि में गिरावट आई है।
- xv. याचिकाकर्ताओं का पहुँच मूल्य का परिकलन वृट्टिपूर्ण है क्योंकि सीमा शुल्क और उप कर को मूल्यांकन योग्य मूल्य के बजाए सीआईएफ मूल्य में जोड़ा गया है जिसके परिणामस्वरूप पहुँच मूल्य कम हुआ।
- xvi. यद्यपि मूल याचिका और वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए संशोधित अनुबंधों में पहुँच मूल्य समान है। अतः संशोधित अनुबंधों में कीमत कटौती श्रृंखला 0-30 प्रतिशत के रूप में दर्शाई गई है। इस नाटकीय वृद्धि को स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, 0-30 प्रतिशत की कीमत कटौती श्रृंखला 5-10 प्वाइंट की स्वीकार्य रेंज की तुलना में बहुत व्यापक है।
- xvii. घरेलू उद्योग ने कच्ची सामग्री की लागतों में गिरावट की सीमा तक अपनी घरेलू बिक्री कीमतें नहीं घटाई हैं जो कि निर्यातकों ने किया है जिसके परिणामस्वरूप पहुँच कीमत घरेलू बिक्री कीमतों से कम रही है।
- xviii. ताइवान से आयातों का प्रभाव अलग नहीं किया गया है और यह नहीं कहा जा सकता है कि विभिन्न क्षति मानदंडों पर कोई भी तथाकथित प्रभाव संबद्ध देशों से आयातों के कारण है।
- xix. यूरोपीय संघ से आयातों का पहुँच मूल्य अधिकतम है।
- xx. याचिकाकर्ता – इंडियन एक्रिलिक्स लि. ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 में प्रभावित वृद्धि के लिए विमुद्रीकरण का उल्लेख किया है।
- xxi. 2016 में घरेलू बिक्री की मात्रा में गिरावट सर्दियों में गर्मी और कम कीमत की चमड़े की जैकेटों की प्राथमिकता में वृद्धि के कारण है।
- xxii. वेतन एवं मजदूरी, कर्मचारी, लगाई गई पूंजी पर आय और लाभ/(हानि) जैसे आर्थिक मानदंड यह दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने वास्तव में जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक वृद्धि देखी है और इसीलिए वे नहीं कह सकते कि उसे क्षति हो रही है।
- xxiii. यूरोपीय समुदाय – भारत से कॉटन टाइप बेड लिनन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क 1 मार्च, 2001 के डब्ल्यूटी/डीएस141/एबी/आर में अपीलिय निकाय ने माना कि शून्यकरण सिद्धांत पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.4 और अनुच्छेद 2.4.2 के अनुसार असंगत है।
- xxiv. कोठारी शुगर एंड केमिकल्स लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (2005 (187) ईएलटी 185 ट्रि डेल) के मामले में माननीय अधिकरण का आदेश, जिस पर याचिकाकर्ताओं ने विश्वास किया है, वर्तमान वास्तविक मैट्रिक्स में नहीं माना जा सकता। माननीय अधिकरण का आदेश इस तथ्य पर आधारित था कि यूरोपीय संघ से आंकड़े अपूर्ण थे और आयातों से कीमत में वृद्धि रुक रही थी।

xxv. यह दोहराया जाता है कि याचिकाकर्ता का निष्पादन विशेष रूप से लाभप्रदता स्पष्ट रूप से दोनों अर्थात् घरेलू उद्योग के निष्पादन और संबद्ध सामानों के आयातों के बीच न तो प्रत्यक्ष और न अप्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करता है। यहां यह उल्लेख करना भी व्यावहारिक है कि याचिकाकर्ताओं की लाभप्रदता उस समय उनके न्यूनतम स्तर पर थी जब संबद्ध देशों से आयात उनके न्यूनतम स्तर पर थे (अर्थात् आधार वर्ष के दौरान), परंतु उनमें संबद्ध देशों से तथाकथित पाटित आयातों में तथाकथित वृद्धि के बावजूद जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि में काफी वृद्धि हुई। यह स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि संबद्ध देशों से आयातों से याचिकाकर्ताओं की लाभप्रदता अथवा उनके वाणिज्यिक निष्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ा है।

xxvi. मात्रात्मक मानदंडों में गिरावट, जब घरेलू उद्योग स्वीकार्य रूप से कठोर मार्जिन स्तरों पर अपनी कीमतें बनाए रख पाया, तथाकथित पाटित आयातों द्वारा हुई नहीं मानी जा सकती।

xxvii. यह देखा जा सकता है कि प्लेइंग कार्ड के मामले में जो मानदंड मौजूद थे, वही एक्रिलिक फाइबर के मामले में मौजूद मानदंडों के लगभग समान हैं। इस प्रकार, उपर्युक्त के मद्देनजर पाटनरोधी शुल्क जारी नहीं रखा जाना चाहिए और वर्तमान जांच इन आधारों पर समाप्त की जानी चाहिए।

xxviii. मात्रात्मक मानदंडों में गिरावट, जब घरेलू उद्योग स्वीकार्य रूप से कठोर मार्जिन स्तरों पर अपनी कीमतें बनाए रख पाया, तथाकथित पाटित आयातों द्वारा हुई नहीं मानी जा सकती।

xxix. क्षति की वस्तुपरक जांच से कीमत मानदंडों सहित घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति की जांच किया जाना आवश्यक हो जाता है जो दर्शाएगा कि कोई क्षति नहीं है, जैसा कि पाटनरोधी नियमावली में परिकल्पित किया गया है। यदि मामले का अनुकूल दृष्टिकोण लिया जाता है तो घरेलू उद्योग द्वारा क्षति का कोई मामला नहीं दर्शाया गया है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

(क) संचयी मूल्यांकन

58. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II (iii) में यह उपबंध है कि यदि एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के हुए आयात के साथ-साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उस स्थिति में ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण करेंगे जब वह यह निर्धारित करें कि:-

क) प्रत्येक देश/संघ क्षेत्र से आयातों के संबंध में पुष्टिकृत पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से हुए आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात की मात्रा की 3 प्रतिशत से कम है वहां संचयी रूप से आयात समान वस्तु के आयातों के सात प्रतिशत से अधिक बनता है; तथा

ख) आयातित वस्तु एवं समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के मद्देनजर आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित है।

59. वर्तमान मामले में प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक पाया गया है; प्रत्येक संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा निर्धारित सीमाओं से अधिक है; और संबद्ध देशों से निर्यात सीधे ही भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा पेश किए गए समान सामानों के साथ तथा परस्पर सीधे ही प्रतिस्पर्द्धा करते हैं। पाटित आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्द्धा की स्थितियों और आयातित उत्पादों तथा समान घरेलू उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्द्धा की स्थितियों के आलोक में उचित है। अतः प्राधिकारी संबद्ध देशों से पाटित आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से मूल्यांकन करना उचित मानते हैं।

ख) क्षति मानदंडों की जांच

60. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर ध्यान दिया है। प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुसार क्षति के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की।

i. मांग और बाजार हिस्से का मूल्यांकन

61. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए भारत में उत्पाद की स्पष्ट खपत अथवा मांग को सभी स्रोतों से

भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और आयात की मात्रा के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार, मूल्यांकित की गई मांग निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

मांग	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. टन	52,739	41,655	48,200	37,749
अन्य उत्पादकों की बिक्री	मी. टन	20,616	20,620	20,585	18,333
आयात – संबद्ध देश	मी. टन	12,596	14,215	16,270	17,951
आयात – अन्य देश	मी. टन	19,253	17,257	18,493	13,445
कुल मांग	मी. टन	1,05,203	93,746	1,03,548	87,479
बाजार हिस्सा	%				
घरेलू उद्योग	%	50	44	47	43
अन्य उत्पादक	%	20	22	20	21
संबद्ध देश	%	12	15	16	21
अन्य देश	%	18	18	18	15
कुल	%	100	100	100	100

62. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग जांच की अवधि में घटी है। मांग 2015-16 में बढ़ने से पूर्व 2013-14 से 2014-15 तक घटी है। तथापि, 2015-16 और पहले के वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में मांग में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्से 2013-14 में 50 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 44 प्रतिशत हो गया। यह फिर थोड़ा-सा दोबारा जांच की अवधि में 43 प्रतिशत तक कम होने से पूर्व 2015-16 में 47 प्रतिशत तक बढ़ गया।

63. अन्य घरेलू उत्पादक का बाजार हिस्सा क्षति की अवधि में कुल मिलाकर स्थिर रहा।

64. दूसरी ओर, संबद्ध देशों का बाजार हिस्सा आधार वर्ष में 12 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 15 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 16 प्रतिशत हो गया और फिर जांच की अवधि में 21 प्रतिशत हो गया।

घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक और कीमत प्रभाव

ii. मात्रात्मक प्रभाव: संबद्ध देशों की आयात मात्रा और हिस्सा

65. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या भारत में पूर्ण दृष्टि से अथवा उत्पादन या खपत के अनुपात में पाटित आयातों में काफी वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों की मात्रा का विश्लेषण निम्नलिखित रूप में किया गया है:

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
आयात मात्रा					
चीन	मी. टन	23	1,529	2,737	2,989
बेलारूस	मी. टन	2,185	2,613	1,322	1,023
यूरोपीय संघ	मी. टन	10,388	10,073	12,034	9,357
उक्रेन	मी. टन	-	-	-	2,195
पेरू	मी. टन	-	-	177	2,387
संबद्ध देश	मी. टन	12,596	14,215	16,270	17,951

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
वे देश, जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है	मी. टन	11,274	12,683	13,670	10,656
अन्य देश	मी. टन	7,979	4,573	4,823	2,790
कुल	मी. टन	31,848	31,471	34,763	31,397
आयात में बाजार हिस्सा					
चीन जन. गण.	%	0.07	4.86	7.87	9.52
बेलारूस	%	6.86	8.30	3.80	3.26
यूरोपीय संघ	%	32.62	32.01	34.62	29.80
उक्रेन	%				6.99
पेरू	%			0.51	7.60
संबद्ध देश	%	39.55	45.17	46.80	57.18
वे देश, जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है		35.40	40.30	39.32	33.94
अन्य देश	%	25.05	14.53	13.87	8.88
कुल	%	100.00	100.00	100.00	100.00
मांग	मी. टन	1,05,203	93,746	1,03,548	87,479
भारतीय उत्पादन	मी. टन	88,211	85,220	1,01,386	90,869
की तुलना में संबद्ध आयात					
मांग	%	12	15	16	21
भारतीय उत्पादन	%	14	17	16	20

66. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों की मात्रा देश में पूरी क्षति की अवधि में, 2015-16 को छोड़कर, जब उसमें पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन के अनुपात में आंशिक गिरावट आई, पूर्ण दृष्टि से तथा खपत एवं उत्पादन के अनुपात में बढ़ी है।

67. भारत में कुल आयातों के संबंध में समग्र रूप से संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा आधार वर्ष में 39.55 प्रतिशत से बढ़कर जांच की अवधि में 57.18 प्रतिशत हो गया।

iii. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

68. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण करने की अपेक्षा है कि क्या तथाकथित आयातित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में काफी कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों का अन्यथा न्यूनीकरण करना अथवा कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य अवधि में हुआ होता।

69. तदनुसार, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कीमत न्यूनीकरण/ह्रास तथा कम कीमत पर बिक्री, यदि कोई है, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) तथा क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच कीमत से की गई है।

कीमत कटौती

70. कीमत कटौती का निर्धारण संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच कीमत की तुलना भारत में घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली से करके किया गया है।

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
निवल बिक्री वसूली	रु./मी. टन	***	***	***	***
समग्र रूप में संबद्ध देश					
पहुँच कीमत	रु./मी. टन	1,64,370	1,71,432	1,33,021	1,15,383
कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***
कीमत कटौती %	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	नकारात्मक	नकारात्मक	0-10	10-15
बेलारूस					
पहुँच कीमत	रु./मी. टन	1,81,152	1,81,901	1,34,812	1,08,167
कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***
कीमत कटौती %	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	नकारात्मक	नकारात्मक	0-5	15-20
चीन जन. गण.					
पहुँच कीमत	रु./मी. टन	2,36,374	1,67,059	1,30,136	1,18,984
कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***
कीमत कटौती %	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	नकारात्मक	0-5	0-5	0-10
यूरोपीय संघ					
पहुँच कीमत	रु./मी. टन	1,60,682	1,69,380	1,33,618	1,18,619
कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***
कीमत कटौती %	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	0-5	नकारात्मक	0-5	0-10
उक्रेन					
पहुँच कीमत	रु./मी. टन	-	-	-	1,17,680
कीमत कटौती	रु./मी. टन	-	-	-	***
कीमत कटौती %	%	-	-	-	***
कीमत कटौती	रेंज	-	-	-	5-15
पेरू					
पहुँच कीमत	रु./मी. टन	-	-	1,23,702	99,173
कीमत कटौती	रु./मी. टन	-	-	***	***
कीमत कटौती %	%	-	-	***	***
कीमत कटौती	रेंज	-	-	0-10	20-30

71. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच कीमत जांच की अवधि में घरेलू बिक्री कीमतों की कटौती कर रही है।

कीमत न्यूनीकरण/ह्रास

72. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का न्यूनीकरण अथवा ह्रास कर रहे हैं, प्राधिकारी क्षति की अवधि में लागतों एवं कीमतों में परिवर्तनों को नोट करते हैं। यह स्थिति निम्नलिखित तालिका के अनुसार दर्शाई गई है:

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
बिक्री की लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	104	76	73
बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	103	84	81
संबद्ध देशों से पहुँच कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	104	81	70

73. बिक्री लागत आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 27 प्रतिशत तक कम हुई है जबकि याचिकाकर्ताओं ने जांच की अवधि में 19 प्रतिशत तक बिक्री कीमत घटाई है। अतः आयातों का घरेलू बिक्री कीमत पर कोई ह्रासमान प्रभाव नहीं है। संबद्ध देशों से आयात की उतराई कीमत चोट की जांच की अवधि में और जांच के दौरान भी घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से अधिक है।

कम कीमत पर बिक्री

74. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई कम कीमत पर बिक्री की स्थिति की भी जांच की है। यह नोट किया जाता है कि पाटित आयातों के कारण जांच की अवधि के दौरान केवल बेलारूस और पेरू से कम कीमत पर बिक्री हुई है। चीन पीआर, यूरोपीय संघ और यूक्रेन से पाटित आयातों के कारण जांच की अवधि के दौरान कोई कम कीमत पर बिक्री नहीं हुई है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	यूनिट	चीन जन. गण.	बेलारूस	यूरोपीय संघ	उक्रेन	पेरू
क्षति रहित कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
जांच की अवधि में आयातों की पहुँच कीमत	रु./मी. टन	1,18,984	1,08,167	1,18,619	1,17,680	99,173
कम कीमत पर बिक्री	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	%	***	***	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	रेंज%	नकारात्मक	0-10	नकारात्मक	नकारात्मक	0-20

छ.4 घरेलू उद्योग के संबंध में आर्थिक मानदंडों की जांच

75. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। समान उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में नियमावली में यह भी उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों,

पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा।

76. तदनुसार, घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक मानदंडों का यहां नीचे विश्लेषण किया गया है।

क) क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग तथा बिक्री

77. प्राधिकारी ने क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री की मात्रा पर विचार किया है तथा निम्नलिखित नोट करते हैं:

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
क्षमता	मी. टन	81,600	81,600	81,600	81,600
उत्पादन	मी. टन	67,783	64,425	80,706	72,536
क्षमता उपयोग	%	83	79	99	89
घरेलू बिक्री	मी. टन	52,739	41,655	48,200	37,749
मांग	मी. टन	1,05,203	93,746	1,03,548	87,479

78. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि:

i. घरेलू उद्योग ने पूरी क्षति की अवधि तथा जांच की अवधि में क्षमता का समान स्तर बनाए रखा है।

ii. यद्यपि उत्पादन में 2014-15 में गिरावट आई, तथापि, जांच की अवधि में पुनः कम होने से पहले 2015-16 में उसमें काफी वृद्धि हुई। क्षमता उपयोग जांच की अवधि में 89 प्रतिशत पर रहने से पूर्व 2015-16 में 99 प्रतिशत तक बढ़ा।

iii. घरेलू बिक्री की मात्रा 2015-16 में बढ़ने से पूर्व और जांच की अवधि में पुनः घटने से पूर्व 2014-15 में घटी।

ख) मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा

79. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभावों की निम्नलिखित रूप में जांच की गई है। यह नोट किया जाता है कि 2015-16 के दौरान थोड़ी-सी वृद्धि को छोड़कर घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा पूरी अवधि में कम हुआ है। दूसरे घरेलू उत्पादक वर्धमान एक्रिलिक्स लि. का बाजार हिस्सा कुल मिलाकर समान स्तर पर रहा है।

बाजार हिस्सा	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग	%	50	44	47	43
अन्य उत्पादक	%	20	22	20	21
संबद्ध देश	%	12	15	16	21
अन्य देश (उन देशों, जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है, सहित)	%	18	18	18	15
कुल	%	100	100	100	100

ग) स्टॉक/मालसूची

80. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के औसत मालसूची स्तरों में बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शाई है। तथापि, मालसूची के स्तरों पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता और इसीलिए प्राधिकारी उसकी जांच कुल बिक्री की मात्रा के साथ करना आवश्यक समझते हैं।

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
औसत मालसूची	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	117	143	172
कुल बिक्री	मी. टन	68,762	62,834	81,314	70,589
कुल बिक्री के समानुपात के रूप में मालसूची	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	128	121	168

81. कुल बिक्री के अनुपात के रूप में मालसूची जांच की अवधि के दौरान थोड़ी-सी प्रतिशतता तक ही बढ़ी है। औसत मालसूची स्तर उत्पादन का लगभग केवल *** के बराबर है।

घ) लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

82. घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में की गई।

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
घरेलू बिक्री की लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	104	76	73
बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	103	84	81
लाभ/हानि	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	87	322	320
लाभ/हानि	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	69	294	229
नकद लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	68	217	170
व्याज और कर पूर्व लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	73	212	165
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	79	239	176

83. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि:

- जांच की अवधि में और पूर्व वर्ष (2015-16) में लाभ/मी. टन काफी बढ़ा है।
- नकद लाभ में जांच की अवधि में गिरावट दर्ज करने से पूर्व 2015-16 के दौरान काफी सुधार हुआ है। तथापि, गिरावट के बाद भी जांच की अवधि में नकद लाभ आधार वर्ष में लाभ से काफी अधिक है।
- नियोजित पूंजी पर आय में क्षति की अवधि में काफी सुधार हुआ है।
- नियोजित पूंजी पर आय जांच की अवधि सहित पूरी क्षति जांच अवधि में एनआईपी निर्धारित करते समय प्राधिकारी द्वारा अनुमत 22 प्रतिशत के मानक से अधिक रही है।
- जांच की अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर आय 50-60 प्रतिशत की सीमा जितनी ज्यादा थी।

ड) रोजगार एवं मजदूरी

84. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जाता है कि कर्मचारियों की संख्या में 2015-16 और जांच की अवधि में आंशिक वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए वेतन और मजदूरी भारी अनुपात में बढ़े हैं।

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि-ए
रोजगार	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	100	103	106
मजदूरी एवं वेतन	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	108	116	146

च) वृद्धि

85. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वृद्धि संबंधी मानदंडों की जांच नीचे दर्शाई गई है:

वृद्धि	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
उत्पादन	%	-	-4.95	25.27	-10.12
बिक्री	%	-	-21.02	15.71	-21.68
क्षमता उपयोग	%	-	-4.82	25.32	-10.10
प्रति यूनिट लाभ/हानि	%	-	-12.67	268.19	-0.46
नियोजित पूंजी पर आय	%	-	-21	160	-63
बाजार हिस्सा - घरेलू उद्योग	%	-			

छ) पाटन और पाटन मार्जिन का स्तर

86. प्रत्येक संबद्ध देश के संबंध में पाटन मार्जिन केवल न्यूनतम से अधिक ही नहीं है, अपितु काफी भी है।

ज) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

87. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतें संबद्ध देशों से पाटित आयातों से प्रभावित नहीं हुई हैं क्योंकि कोई कीमत हास नहीं है। घरेलू उद्योग अच्छा लाभ और नियोजित पूंजी पर आय अर्जित कर रहा है। जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री मूल्य प्राधिकारी द्वारा निर्धारित गैर-हानिकारक मूल्य की तुलना में काफी अधिक थी।

झ) नए निवेश जुटाने की क्षमता

88. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग अच्छा लाभ और नियोजित पूंजी पर अच्छी आय अर्जित कर रहा है, अतः उसमें नए निवेश जुटाने की क्षमता है।

छ.5 क्षति और क्षति मार्जिन की मात्रा

89. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों की क्षति रहित कीमत की संबद्ध देश से निर्यातों के पहुँच मूल्य से तुलना करने पर वह जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक क्षति मार्जिन दर्शाती है।

देश	उत्पादक	निर्यातक	क्षति रहित कीमत अमेरिकी डॉलर प्रति मी. टन	पहुँच मूल्य अमेरिकी डॉलर प्रति मी. टन	क्षति मार्जिन अमेरिकी डॉलर प्रति मी. टन	क्षति मार्जिन भारतीय रुपए मी. टन	क्षति मार्जिन %
			अमेरिकी डॉलर/मी. टन	अमेरिकी डॉलर/मी. टन	अमेरिकी डॉलर/मी. टन	%	रेंज
चीन जन. गण.	मैसर्स जिलिन किफेंग केमिकल फाइबर कं. लि.	मैसर्स जिलिन किफेंग केमिकल फाइबर कं. लि.	***	***	***	***	(10)-0
चीन जन. गण.	अन्य सभी	अन्य सभी	***	***	***	***	(10)-0
बेलारूस	ओपन ज्वाइंट – स्टॉक कंपनी नफटान	ओपन ज्वाइंट – स्टॉक कंपनी नफटान	***	***	***	***	0-10
बेलारूस	अन्य सभी	अन्य सभी	***	***	***	***	15-25
यूरोपीय संघ	डेलोन जीएमबीएच	डेलोन जीएमबीएच	***	***	***	***	(15)-0
यूरोपीय संघ	अन्य सभी	अन्य सभी	***	***	***	***	(5)-0
उक्रेन	सभी	सभी	***	***	***	***	(10)-0
पेरू	सभी	सभी	***	***	***	***	5-15

ज. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात विवरण संबंधी अनुरोध

90. हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन पश्चात अनुरोध प्राप्त हुए हैं। उनमें उठाए गए अधिकतर मुद्दे जांच के दौरान पूर्व में पहले ही उठा दिए गए हैं और उनका उचित रूप से समाधान भी कर दिया गया है। अतिरिक्त अनुरोधों का विश्लेषण निम्नलिखित रूप में किया गया है:

ज.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

91. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. होमो पॉलीमर एक्रिलिक फाइबर ही है और एक पृथक उत्पाद नहीं है तथा उसे विचाराधीन उत्पाद से अलग नहीं किया जाना चाहिए। विगत में की गई कई जांचों में प्राधिकारी द्वारा विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में कोई पृथक्करण नहीं किया गया है।

ii. वर्तमान जांच में जांच की अवधि वर्ष 2016 के अंतर्गत है, जो चीनी अधिगम नयाचार की समाप्ति से ठीक पहले है। किसी भी दशा में अधिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(i) के प्रावधान अब भी लागू हैं और उन पर चीन के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु विचार किया जाना चाहिए।

iii. प्राधिकारी ने सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य निर्मित किया है और उसके लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर विचार किया है। तथापि, आईएचएस केमिकल रिपोर्ट के अनुसार एशिया (सुदूरपूर्व) क्षेत्र में विद्यमान एक्रिलिक फाइबर की कीमत का साक्ष्य, जो पहले प्रस्तुत किया गया है उस पर विचार नहीं किया गया है। इस बात का प्रकटन विवरण में कोई तर्क नहीं है कि ऐसी सूचना को स्वीकार क्यों नहीं किया जा सकता तथा कानून के तहत निर्धारित क्रम को क्यों नहीं अपनाया जाना चाहिए।

- iv. मांग में गिरावट के बावजूद आयात मात्रा में वृद्धि हुई है। यह तथ्य यह मानने के लिए पर्याप्त है कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- v. संबद्ध आयातों की मात्रा का भारत में आयातों का काफी हिस्सा है और समग्र रूप से भारत में कुल आयातों का यह हिस्सा आधार वर्ष में 39.55 प्रतिशत से बढ़कर जांच के अवधि में 57.18 प्रतिशत हो गया।
- vi. पूर्व का यह अनुरोध कि कीमत कटौती का निर्धारण केवल उन लेन-देनों पर विचार करते हुए किया जाना चाहिए, जिनके आयात की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम हो, यद्यपि प्राधिकारी ने नोट किया, तथापि उसकी जांच नहीं की गई है।
- vii. बिक्री लागत 2014-15 तक बढ़ी, परंतु उसके बाद उसमें गिरावट आई। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में भी वही प्रवृत्ति अपनाई, परंतु संबद्ध सामानों की पहुँच कीमत बिक्री लागत तथा बिक्री कीमत से कम रही।
- viii. कीमत प्रभाव के निर्धारण में पाटनरोधी नियमावली में एक आवश्यकता के रूप में "अथवा" है और न्यूनीकरण/ह्रास तथा कीमत कटौती के बीच "और" नहीं है।
- ix. घरेलू उद्योग के उत्पादन में 2015-16 तक सुधार हुआ है और उसके बाद जांच की अवधि में उसमें गिरावट आई है। बिक्री में क्षति की अवधि में काफी गिरावट आई है और यह गिरावट मांग में गिरावट से काफी अधिक है। क्षमता उपयोग में जांच की अवधि से पूर्व के वर्ष की तुलना में गिरावट आई है।
- x. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वर्तमान मामले में प्रतिकूल मात्रात्मक प्रभाव का निष्कर्ष निकालते समय घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न मानदंडों का सह-संबंध बनाएं। आयातों ने मांग की प्रवृत्ति नहीं अपनाई है। यहां तक कि जब मांग में गिरावट आई तो आयातों में वृद्धि हुई।
- xi. मालसूची में पूर्ण दृष्टि से तथा घरेलू बिक्री के अनुपात में दोनों में वृद्धि हुई है। कानूनी आवश्यकता यह है कि क्या घरेलू उद्योग के निष्पादन में मालसूची के संबंध में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के लिए अपनी मालसूची बढ़ाने का उस समय कोई कारण नहीं था जब उसका उत्पादन और बिक्री गिर रहे थे।
- xii. घरेलू उद्योग को उत्पादन लंबित रखने के लिए मजबूर किया गया है और उसे उत्पादन एवं बिक्री में गिरावट के कारण भारी क्षति हुई है। यह भी देखा जाएगा कि उत्पादन में गिरावट और मालसूची में वृद्धि के बीच सीधा सह-संबंध है।
- xiii. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा क्षति की अवधि में भारी मात्रा में कम हुआ है, जबकि संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में समग्र रूप से मांग को पूरी करने की पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद भी गिरावट आई है।
- xiv. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर आय में सुधार हुआ है। इस प्रकार, पाटन का प्रभाव इन मानदंडों पर नहीं दिखाई देता। घरेलू उद्योग ने लाभ के संबंध में अपने लंबे प्रतिकूल निष्पादन के मद्देनजर कच्ची सामग्री की कीमतों में कमी के समय आंशिक रूप से कीमत में गिरावट की।
- xv. विभिन्न स्रोतों से सतत/नवीनीकृत पाटन/पाटन के लंबे इतिहास से याचिकाकर्ताओं को ऐसे सतत पाटन के कुप्रभावों से उभरने के लिए और अपने शेयरधारकों को एक बार भी लाभांश देने के लिए एक भी अवसर नहीं मिला।
- xvi. दी गई मजदूरी और कर्मचारियों की संख्या क्षति की अवधि में बढ़ी है। ये पूर्णतः संबद्ध सामानों के निष्पादन पर निर्भर नहीं हैं और कंपनी के समग्र प्रचालनों तथा अर्थव्यवस्था से शासित होते हैं। वे पाटन के प्रतिकूल प्रभाव को नहीं दर्शा सकते।
- xvii. घरेलू उद्योग कोई भी नया निवेश करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि वह विभिन्न देशों से आयातों के पाटन का सामना कर रहा है।
- xviii. संबद्ध देशों से औसत आयात कीमत घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से काफी कम है जो काफी क्षति मार्जिन दर्शा रही है।

- xix. दूसरे देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात मात्रा एवं मूल्य, दोनों दृष्टि से लगाए हैं और थाइलैंड से आयातों पर पहले ही शुल्क लग रहा है। लगभग 57 प्रतिशत आयात संबद्ध देशों से हैं।
- xx. संबद्ध उत्पाद की मांग में गिरावट है। तथापि, संबद्ध देशों से आयात जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि में बढ़े हैं। इस प्रकार, घटती हुई मांग की स्थिति में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है।
- xxi. विगत जांचों में, यथा – विस्कोस स्टेपल फाइबर, फ्रंट एक्सल बीम, जिनमें विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में गिरावट आई थी, प्राधिकारी ने माना कि मांग में गिरावट की स्थिति में आयातों में वृद्धि से यह सिद्ध हुआ कि पाटन से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- xxii. एनआईपी का विस्तृत विवरण प्राधिकारी द्वारा प्रकट किया जाना होता है।
- xxiii. प्राधिकारी द्वारा मानी गई एनआईपी काफी कम रही है जिससे अनुचित रूप से कम क्षति मार्जिन बना है।
- xxiv. प्राधिकारी संबद्ध देशों से निर्यातकों/उत्पादकों की सत्यापन रिपोर्ट का अगोपनीय रूपांतर प्रकट करें ताकि परिकलित पाटन मार्जिन के संबंध में सार्थक प्रक्रिया दी जा सके।
- xxv. प्रकटन विवरण यह भाव दर्शाता है कि निम्नलिखित को तथ्यों के रूप में माना गया है, जबकि ये मानदंड हैं: आयात मात्रा में प्रवृत्तियाँ, कीमत प्रभाव, क्षति का संचयी मूल्यांकन। घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में विचाराधीन अनिवार्य तथ्य प्रकटन विवरण में प्रकट नहीं किए गए हैं।
- xxvi. पाटनरोधी शुल्क का स्वरूप पाटनरोधी शुल्क की निर्धारित मात्रा होना चाहिए।
- xxvii. पाटनरोधी शुल्क अंतिम निर्धारण में अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए। रुपए का काफी मूल्यह्रास हुआ है और इसीलिए निश्चयात्मक शुल्क कृपया अमेरिकी डॉलर में व्यक्त किए जाएं।

ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

92. उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. डाउनस्ट्रीम उद्योग किसी अन्य घरेलू उत्पादक द्वारा विशेष प्रकार के एक्रिलिक फाइबर की अनुपलब्धता/विनिर्माण न किए जाने के कारण विशेष एक्रिलिक फाइबर की कई किस्मों का आयात करने के लिए मजबूर है। विशिष्ट गुणवत्ता/विशेषता के निचले स्तर के सामानों के उत्पादन के लिए एक्रिलिक फाइबर की विशिष्ट किस्मों की आवश्यकता एवं अपेक्षा आयात कीमत से शासित नहीं होती है बल्कि विशिष्ट विशेषता वाले एक्रिलिक फाइबर के कारण होती है।
- ii. इन विशेषता वाले फाइबरों की आवश्यकता एंटी-पायलिंग, मुलायम एवं विलासिता वाली बनावट आदि जैसी गुणवत्ताओं के लिए होती है जिसे भारतीय उत्पादकों द्वारा उत्पादित एक्रिलिक फाइबर का प्रयोग करके प्राप्त करना संभव नहीं है। अतः इन विशेषता वाले फाइबरों के आयात को इस जांच के प्रयोजन के लिए विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।
- iii. प्रथम गुणवत्ता के ग्रेडों और कम गुणवत्ता के ग्रेडों के बीच अंतर है। इन्हें "समान वस्तु" नहीं माना जा सकता क्योंकि वे तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता, उत्पाद विशिष्टियों, प्रकार्य एवं अंतिम प्रयोग, अंतिम प्रयोक्ता की आवश्यकता और कीमत के संबंध में भिन्न हैं। प्राधिकारी घटिया ग्रेड को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग कर सकते हैं।
- iv. ओजेएससी नाफटान का सामान्य मूल्य प्रश्नावली में दी गई सूचना के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए क्योंकि बेलारूस को भारत सरकार द्वारा एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में मान्यता दी गई थी।
- v. ओजेएससी नाफटान प्राधिकारी द्वारा परिकलित पाटन मार्जिन से सहमत नहीं हैं। प्रश्नावली में ओजेएससी नाफटान द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार पाटन मार्जिन नकारात्मक है। इस प्रकार, ओजेएससी, नाफटान द्वारा उत्पादित एक्रिलिक फाइबर के विरुद्ध जांच को रद्द किया जाना चाहिए।

- vi. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे सुबामेरिकाना डि फाइबर्स एस. ए. द्वारा किए गए अनुरोधों को केवल निर्यात कीमत को निर्मित करने के बजाए निर्यात की कीमत का परिकलन करने के लिए ध्यान में रखें। तदनुसार, सुबामेरिकाना को भी पाटन एवं क्षति का अलग-अलग मार्जिन प्रदान किया जाए।
- vii. चीन जन. गण., यूरोपीय संघ और उक्रेन के लिए नकारात्मक क्षति मार्जिन परिकलित किया गया है। यह दर्शाता है कि केवल 19 प्रतिशत संबद्ध आयात क्षति रहित कीमत से कम हैं। उन कम कीमत के आयातों के कारण क्षति होने का कोई कारण नहीं है जो एनआईपी से अधिक हैं।
- viii. यद्यपि, आयातों की प्रवृत्ति का मद-वार विश्लेषण यह दर्शाता है कि आयातों में वृद्धि हुई है, तथापि, बड़े हुए आयातों की प्रवृत्ति पूरी क्षति की अवधि के दौरान सिद्ध नहीं है (वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए भारत में आयातों में कमी आई है)।
- ix. इस तथ्य से कि चीन जन. गण., यूरोपीय संघ और उक्रेन के मूल के आयातों (संबद्ध देशों से कुल आयातों के 75 प्रतिशत से अधिक वाले) के लिए कोई क्षति मार्जिन नहीं है। तथापि, मात्रात्मक एवं कीमत प्रभाव घरेलू उद्योग को क्षति तथा संबद्ध देशों से कम कीमत पर आयातों के बीच कोई कारणात्मक संपर्क स्थापित नहीं करते।
- x. उस तरीके में कोई अंतर्निहित विरोध नहीं है जिसमें कम कीमत पर बिक्री संबंधी निष्कर्ष निकाला गया है। प्रकटन विवरण में उल्लेख किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद की कम कीमतों पर बिक्री हुई है। तथापि, तालिका दर्शाती है कि संबद्ध देशों से भारत में 75 प्रतिशत से अधिक आयातों से कम कीमत पर कोई बिक्री नहीं हुई है।
- xi. घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में नियत वृद्धि एवं कमी का पैटर्न है।
- xii. चूंकि, प्रमुख वित्तीय मानदंडों, यथा - लाभ, नकद प्रवाह और नियोजित पूंजी पर आय में पर्याप्त रूप से सुधार हुआ है, अतः आर्थिक संकेतक घरेलू उद्योग को क्षति की मौजूदगी होने का पूरा साक्ष्य प्रदान नहीं करते।
- xiii. प्रकटन विवरण में प्रयोक्ताओं, आयातकों संबंधी इन शुल्कों के प्रभाव के संबंध में कोई विश्लेषण नहीं दिया गया है। यदि एक्रिलिक फाइबर पर शुल्क लगाया जाता है तो एक्रिलिक यार्न के लिए स्पिनिंग कंपनियों की लागत बढ़ जाएगी।
- xiv. शुल्क का प्रभाव रुग्ण स्पिनिंग उद्योग द्वारा खपाया जाना होगा क्योंकि बुनकरों और सलाईकारों (एक्रिलिक यार्न के अंतिम प्रयोक्ताओं) के पास भारत से बाहर के स्रोतों से उपलब्ध वैकल्पिक स्रोत नहीं हैं।
- xv. बेलारूसियन कंपनियों द्वारा उत्पादित एक्रिलिक फाइबर की आयात मात्रा कम हुई है और घरेलू उद्योग को उससे कोई क्षति नहीं होता, अथवा उससे कोई खतरा नहीं होता।
- xvi. विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से प्रयोक्ताओं को नुकसान होगा और विचाराधीन उत्पाद के अधिसंख्य लघु अंतिम प्रयोक्ताओं पर काम बंद हो जाएगा।
- xvii. उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री क्षति की अवधि में बाजार प्रवृत्ति के अनुसार चली है।
- xviii. जांच की अवधि में 2015-16 की तुलना में विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में संकुचन हुआ है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से ने वही प्रवृत्ति अपनाई है। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा परस्पर फाइबर प्रतिस्पर्द्धा के आलोक में और प्रयोक्ता उद्योग द्वारा विशिष्टता वाले फाइबर की आवश्यकता के आलोक में भी देखे जाने की आवश्यकता है।
- xix. मात्रात्मक प्रभाव निर्धारित करते समय प्राधिकारी को नोट करना चाहिए कि संबद्ध आयातों में वृद्धि अधिकतर थाइलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि जैसे देशों से विभिन्न एफटीए के कारण आयातित सामग्री की स्वतंत्र रूप से उपलब्धता की वजह से बढ़ते हुए प्रतिस्पर्द्धा बाजार में संगत बने रहने के लिए विशेषता वाले यार्न के उत्पादन के लिए विशेषता वाले फाइबर की आवश्यकता के कारण है।
- xx. भारत में पहुँच कीमत के साथ एनएसआर की सामान्य तुलना कीमत कटौती के संबंध में सही हिसाब नहीं बताएगी क्योंकि याचिकाकर्ताओं की घरेलू बिक्री कीमतें एनआईपी से काफी अधिक हैं।

- xxi. घरेलू उद्योग ने अपनी निर्यात बिक्री पर सब्सिडी देने के लिए घरेलू बाजार में प्रीमियम कीमत का सहारा लिया है और घरेलू उद्योग की काफी अधिक कीमत के साथ कीमत कटौती की ऐसी जांच से टेढ़े विश्लेषण और विपरीत स्थिति होगी।
- xxii. न तो कीमत न्यूनीकरण/ह्रास है और न ही कम कीमत पर बिक्री है। आयातों में इस संबंध में याचिकाकर्ताओं के निष्पादन का कीमत पर कोई प्रभाव नहीं दर्शाया है।
- xxiii. घरेलू उद्योग का बिक्री निष्पादन मांग में संकुचन और परस्पर फाइबर प्रतिस्पर्द्धा को ध्यान में रखते हुए विश्लेषित किए जाने की आवश्यकता है।
- xxiv. बाजार हिस्से में गिरावट को भी मांग में संकुचन, परस्पर फाइबर प्रतिस्पर्द्धा और विशेषता वाले फाइबर के आयात की आवश्यकता के आलोक में देखे जाने की आवश्यकता है जिसका कि अन्यथा घरेलू रूप से उत्पादन नहीं किया जाता है।
- xxv. जांच की अवधि में कुल आयात का केवल 20 प्रतिशत बेलारूस और पेरू से था और शेष यूरोपीय संघ, उक्रेन और चीन जन. गण. से थे। ऐसे परिदृश्य में, दस्तावेज पर सकारात्मक क्षति मार्जिन के आधार पर बेलारूस और पेरू पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का कोई निर्णय इस तथ्य को देखते हुए अतार्किक और असंगत होगा कि घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है।
- xxvi. भारत के घरेलू उत्पादक उत्पादन प्रौद्योगिकी में पीछे हैं और विशेषता वाले फाइबर का उत्पादन करने में अक्षम हैं। परिणामस्वरूप प्रयोक्ता उद्योग विभिन्न एफटीए के कारण कठोर प्रतिस्पर्द्धा की पृष्ठभूमि में बाजार में संगत बने रहने के प्रयोजन के लिए उसका आयात करने के लिए मजबूर है।
- xxvii. भारत में एक्रिलिक फाइबर के भारतीय उत्पादकों और प्रयोक्ता उद्योग के बीच हितों का सीधा टकराव है। घरेलू उद्योग प्रयोक्ता उद्योग अर्थात् ग्राहक और प्रतिस्पर्द्धा के साथ दोहरा संबंध रखता है। घरेलू उद्योग केवल अधिक लाभ अर्जित करने के लिए ही प्रयोक्ता उद्योग से संबद्ध सामानों के लिए उच्चतर कीमतें नहीं लगा रहा है बल्कि निचले बाजार में प्रयोक्ता उद्योग की आर्थिक बढत प्राप्त करने के लिए भी ये कीमतें लगा रहा है जो निश्चित रूप से प्रतिबंधात्मक प्रथा प्रतिस्पर्द्धा विरोधी परिपाटियों के योग्य बनता है।
- xxviii. ताइवान से आयातों के संबंध में संज्ञान लिया जाना चाहिए था जो कि बेलारूस से आयातों से कहीं अधिक थे। ताइवान से आयातों का हिस्सा कुल आयातों में लगभग 5 प्रतिशत रहा और ताइवान से कीमत संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की कीमत से कम था।
- xxix. पूर्वाग्रह के बिना यदि घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से आयातों के कारण क्षति का दावा करता है तो उन्हें सबसे पहले यह सिद्ध करने की आवश्यकता है कि ताइवान से आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हो रही थी, यद्यपि वे आयात न्यूनतम स्तर से अधिक थे तथा संबद्ध देशों की तुलनीय कीमतों से कम भी थे।
- xxx. ताइवान को जांच के क्षेत्र में शामिल किए जाने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस संबंध में कोई तर्क नहीं दिया गया है अथवा यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि ताइवान से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के कारण भारत में पाटन हो रहा है। अतः ताइवान को इस जांच के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।
- xxxi. सुवामेरिकाना डि फाइबर्स एस. ए. ने पाटनरोधी नियमावली और व्यापार नोटिसों के अनुसार गोपनीयता की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। अतः याचिकाकर्ता की अत्यधिक गोपनीयता के दावे, जो सुवामेरिकाना के संबंध में किया गया है, को नकार दिया जाना चाहिए।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

93. ऊपर उठाए गए एवं संगत माने गए मुद्दों के लिए प्राधिकारी द्वारा की गई जांच निम्नलिखित है:

- i. विचाराधीन उत्पाद एक्रिलिक फाइबर है। यह एक्रिलोनाइट्राइल यूनियो (उत्पादन के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री) के भाग से कम से कम 90 प्रतिशत पर सम्मिश्रित सिंथेटिक पॉलीमर की एक लंबी श्रृंखला है। एक्रिलिक फाइबर में एक्रिलिक स्टेपल फाइबर, एक्रिलिक टॉ तथा एक्रिलिक टॉप शामिल होता है जो सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों में एक्रिलिक फाइबर के रूप में

जाने जाते हैं। एक्रिलिक स्टेपल फाइबर और एक्रिलिक टॉ के बीच केवल लंबाई का अंतर होता है। 2 मीटर से अधिक लंबाई के मामले में इसे टॉ जाना जाता है और कटी हुई लंबाई के मामले में इसे स्टेपल फाइबर के रूप में जाना जाता है।

ii. एक्रिलिक फाइबर ऊन जैसा महसूस होना वाला हल्का मुलायम और गर्म होता है। इसके फाइबर बहुत ही मुलायम होते हैं और प्राकृतिक एवं अन्य सिंथेटिक फाइबरों, दोनों की तुलना में एसिड तथा अल्कालीज में अत्यधिक प्रतिरोधकता दर्शाते हैं।

iii. एक्रिलिक फाइबर 4 अंकों के स्तर पर उप शीर्ष 5501, 5503 और 5506 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 55 के अंतर्गत वर्गीकृत है। यह उत्पाद एचएस कोड 550130, 550330 और 550630 के अंतर्गत शामिल है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और उत्पाद के क्षेत्र पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।

iv. जहां तक कम गुणवत्ता अथवा दोयम ग्रेडों का मुद्दा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद को केवल गुणवत्ता के आधार पर जांच के क्षेत्र से अलग नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों ने इस बात का कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि ये कम गुणवत्ता के ग्रेड घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित समान वस्तु से प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर रहे हैं। अतः, प्राधिकारी इन ग्रेडों को अलग न करने का निर्णय लेते हैं।

v. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि घरेलू उद्योग 100 प्रतिशत एक्रिलोनाइट्राइल से युक्त होमो पॉलीमर एक्रिलिक फाइबर का विनिर्माण नहीं करता। मैसर्स पशुपति एक्रिलिन लि. से एक पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उन्होंने यह उल्लेख किया है कि वे होमो पॉलीमर एक्रिलिक स्टेपल फाइबर का उत्पादन नहीं करते। अतः प्राधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र "100 प्रतिशत एक्रिलोनाइट्राइल से युक्त होमो पॉलीमर एक्रिलिक फाइबर" को छोड़कर एक्रिलिक फाइबर के सभी रूप हैं।

vi. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करने के बाद प्राधिकारी का यह मानने का इरादा है कि भारत में भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध सामानों में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामान भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एक्रिलिक फाइबर आयातित एक्रिलिक फाइबर का तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है। प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है। तथापि, प्राधिकारी "100 प्रतिशत एक्रिलोनाइट्राइल से युक्त होमो पॉलीमर एक्रिलिक फाइबर" को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग करने का निर्णय लेते हैं।

vii. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि घरेलू उत्पादक उत्पादन प्रौद्योगिकी में पीछे हैं और विशेषता वाले फाइबर का उत्पादन करने में अक्षम हैं। अतः यह नहीं दर्शाया गया है कि घरेलू उद्योग को संभावित क्षति प्रौद्योगिकी में विकास के कारण हो सकती है।

viii. बाजार अर्थव्यवस्था के स्तर संबंधित दावे के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. से किसी निर्यातक/उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था के स्तर का दावा नहीं किया है। चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग की इष्टतम लागत तथा सर्वाधिक दक्ष घटक के उपभोग मानदंडों तथा पाटनरोधी नियमावली के तहत प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लाभ और प्राधिकारी की सतत परिपाटी पर विचार करते हुए निर्मित किया गया है।

ix. ओजेएससी नाफ्टान द्वारा उनके पाटन मार्जिन निर्धारण के संबंध में किए गए अनुरोध के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि ओजेएससी नाफ्टान के लिए पाटन मार्जिन पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्धारित किया गया है।

x. सुबामेरिकाना डि फाइबर्स एस. ए. द्वारा उनके लिए अलग-अलग पाटन एवं क्षति मार्जिन निर्धारित करने में किए गए अनुरोध के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी के लिए भारत में निर्यात श्रृंखला में शामिल सभी पक्षकारों के भाग न लेने के कारण अलग-अलग पाटन एवं क्षति मार्जिन निर्धारित करना संभव नहीं है।

xi. ताइवान को जांच के क्षेत्र में शामिल करने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह दर्शाने के लिए कोई तर्क अथवा साक्ष्य नहीं दिया गया है कि ताइवान से विचाराधीन उत्पाद के आयातों का भारत में पाटन हो रहा है। अतः ताइवान को इस जांच के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।

- xii. जहां तक आयातों में वृद्धि और मांग में गिरावट के कारण क्षति होने का संबंध है, प्राधिकारी यह पाते हैं कि क्षति की जांच में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अंतर्गत सभी संगत कारकों की जांच शामिल है।
- xiii. इस अनुरोध के संबंध में कि कीमत कटौती का निर्धारण केवल उन लेन-देनों पर विचार करके किया जाना चाहिए कि जिन आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है, प्राधिकारी यह पाते हैं कि यह निर्दिष्ट प्राधिकारी की स्थापित परिपाटी है कि कीमत कटौती का विश्लेषण सभी आयात लेन-देनों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।
- xiv. जहां तक इस दावे का संबंध है कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित एनआईपी प्रकट की जानी चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एनआईपी का विस्तृत परिकलन घरेलू उद्योग को प्रकटन विवरण के साथ प्रकट किया गया था।
- xv. जहां तक इस दावे का संबंध है कि निर्यातकों/उत्पादकों की सत्यापन रिपोर्ट प्रकट की जानी चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन सत्यापन रिपोर्टों में निर्यातकों की गोपनीय सूचना होती है और यह रिपोर्ट किसी भी पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी द्वारा प्रकट नहीं की जाती है।
- xvi. सूचना की गोपनीयता के संबंध में प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता के दावों की जांच की है। प्राधिकारी ने याचिकाकर्ताओं द्वारा और विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए गोपनीयता के दावों पर विचार किया है तथा उसके संबंध में संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों की अनुमति दी है। प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार अनुरोध पर, निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर से युक्त सार्वजनिक फाइल सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई है।
- xvii. जहां तक इस दावे का संबंध है कि क्षति संबंधी मानदंडों पर प्राधिकारी द्वारा किए गए निष्कर्ष को प्रकटन विवरण में प्रकट किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार जारी किया जाता है जिससे उन्होंने विचाराधीन अनिवार्य तथ्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किए हैं जो अंतिम निर्णय का आधार बनेंगी।
- xviii. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुसार क्षति के संबंध में घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में क्षति की अवधि में पर्याप्त सुधार हुआ है। जांच की अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर आय 50-60 प्रतिशत की सीमा जितनी ज्यादा थी। जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित एनआईपी से काफी अधिक थी। आयातों से घरेलू बिक्री कीमत पर कोई न्यूनीकरण प्रभाव नहीं था।
- xix. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यद्यपि, संबद्ध देशों से पूरी मात्रा में तथा भारत में उत्पादन एवं खपत के संबंध में पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है, तथापि, चीन जन. गण., यूरोपीय संघ और उक्रेन से जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग के लिए प्राधिकारी द्वारा निर्धारित एनआईपी से अधिक रही है। इन तीन संबद्ध देशों से आयात सभी संबद्ध देशों से कुल मिलाकर संबद्ध सामानों के कुल आयातों का लगभग 81 प्रतिशत है। अतः सभी संबद्ध देशों से उन्हें साथ मिलाकर आयातों के लगभग 81 प्रतिशत से घरेलू उद्योग को क्षति होना नहीं कहा जा सकता।
- xx. सभी क्षति संबंधी मानदंडों का अनुकूल विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घरेलू उद्योग को पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित किए गए अनुसार वास्तविक क्षति नहीं हो रही है।

छ.6 क्षति संबंधी निष्कर्ष

94. पाटनरोधी नियमावली के तहत दी गई वास्तविक क्षति से संबंधित विभिन्न मानदंडों पर विचार करते हुए प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:

क. संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में पूर्ण रूप से तथा भारत में उत्पादन एवं खपत के संबंध में वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन भी सकारात्मक और काफी है। तथापि, चीन जन. गण., यूरोपीय संघ और उक्रेन से जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग के लिए प्राधिकारी द्वारा निर्धारित एनआईपी से अधिक रही है। इन तीन संबद्ध देशों से आयात सभी संबद्ध देशों से कुल मिलाकर संबद्ध सामानों के कुल आयातों का लगभग 81 प्रतिशत है।

अतः सभी संबद्ध देशों से उन्हें साथ मिलाकर आयातों के लगभग 81 प्रतिशत से घरेलू उद्योग को क्षति होना नहीं कहा जा सकता। संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग के लिए किसी भी किस्म का कीमत न्यूनीकरण भी नहीं हुआ है।

ख. संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच कीमत पूरी क्षति जांच की अवधि तथा जांच की अवधि के दौरान भी घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से अधिक रही है।

ग. यद्यपि, घरेलू उद्योग की क्षमता क्षति की अवधि के दौरान उसी स्तर पर रही है, तथापि, घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्से जैसे अन्य मानदंडों में वैकल्पिक वर्षों में गिरावट एवं वृद्धि का नियत पैटर्न अपनाया है।

घ. लाभ, नकद लाभ तथा नियोजित पूंजी पर आय में क्षति की अवधि में काफी सुधार हुआ है।

ङ. जांच की अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर आय 50-60 प्रतिशत की सीमा जितनी ज्यादा थी।

च. जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित एनआईपी से काफी अधिक थी।

95. उपर्युक्त के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटनरोधी नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार जांच की अवधि के दौरान वास्तविक क्षति नहीं हो रही है।

ज. कारणात्मक संपर्क एवं अन्य कारक

96. जैसा कि प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला है कि घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान कोई वास्तविक क्षति नहीं हो रही है, प्राधिकारी कोई कारणात्मक संपर्क एवं गैर संबद्ध विश्लेषण नहीं कर रहे हैं।

झ. सिफारिश

97. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों की जांच करने पर तथा उपर्युक्त तथ्यों, परिस्थितियों और विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वास्तविक क्षति नहीं हो रही है। उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करना उपयुक्त नहीं मानते तथा एतद्वारा इस जांच को पाटनरोधी नियमावली के नियम 14(ख) के अनुसार रद्द करते हैं।

ञ. आगे की प्रक्रिया

98. इस अंतिम जांच परिणाम की अधिसूचना के कारण केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2018

FINAL FINDINGS

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of 'Acrylic Fibre', originating in or exported from China PR, Belarus, Ukraine, EU and Peru.

No. 14/50/2016-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules thereof, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD rules) thereof M/s Indian Acrylics Ltd. and M/s Pasupati Acrylon Ltd. (hereinafter also referred to as "the Petitioners" or "the Domestic Industry") have filed an application before the Designated Authority (hereinafter

also referred to as “the Authority”) in accordance with the Act and the AD Rules, for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Acrylic Fibre” (also referred to as “the subject goods”), originating in or exported from China PR, Belarus, Ukraine, EU and Peru (also referred to as “the subject countries”) and requested for levy of anti-dumping duties on the subject goods.

2. Whereas, the Authority, on the basis of *prima facie* evidence submitted by the Petitioners, issued a public notice vide Notification No. 14/50/2016 -DGAD dated 19th April, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject investigations in accordance with the Rule 6(1) of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

A. PROCEDURE

3. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to this subject investigation:

i. The Authority notified the embassies of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule 5(5) of the AD Rules.

ii. The Authority issued a Notification dated 19th April, 2017, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries.

iii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the embassies of the subject countries in India, known producers/exporters from the subject countries, known importers/users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification in accordance with Rule 6(2) of the AD Rules.

iv. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters, known importers and to the embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules.

v. The Authority sent exporter’s questionnaire to the following known producers/exporters in the subject countries, whose details were made available by the applicant, to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

- a. Montefibre Spa, Italy (EU)
- b. International Rayon and Synthetic Fibres Committee, Belgium
- c. Acordis AG, Germany
- d. Dralon GmbH, Germany
- e. Markische Faser AG, Germany
- f. International Rayon and Synthetic Fibres Committee, Belgium
- g. Acordis UK Ltd.
- h. Neftokhim Petrochemical Complex, Bulgaria
- i. LUKOIL Company, Bulgaria
- j. JSC POLYMIR, Belarus
- k. Anqing Petrochemical, China PR
- l. Pumica Trading Corp Ltd., Latvia
- m. Jilin Qifeng Chemical Fiber Co. Ltd., China PR
- n. Jilin Jimont Acrylic Fiber Co. Ltd., China PR
- o. Shanghai Petrochemical, China PR
- p. Qilu Petrochemical, China PR
- q. Sudamericana de Fibras S.A, Peru

vi. The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from the subject countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire

sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.

vii. The following producers/exporters from the subject countries filed exporter's questionnaire response in the prescribed format:

- a. Sudamericana de Fibras S.A (Producer) – Peru
- b. Jilin Qifeng Chemical Fiber Co. Ltd. (Producer/Exporter)– China PR
- c. Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. (Producer) – China PR
- d. China Jinshan Associated Trading Corporation(Exporter)– China PR
- e. Dralon GmbH, Germany (Producer/Exporter) – European Union
- f. Open Joint-Stock Company Naftan (Producer/Exporter)-Belarus

viii. The Authority forwarded a copy of the Initiation Notification to the following known importers/users/user associations, whose names and addresses were made available to the Authority, of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within the time limit prescribed by the Authority in accordance with the Rule 6(4):

- a. Rajasthan Spinning & Weaving Mills Ltd., New Delhi
- b. Vardhaman Spinning & General Mills, Ludhiana
- c. Deepak Spinners Ltd., Chandigarh
- d. Malwa Cotton Spinning Mills Ltd., Ludhiana
- e. Shiwalika Spg. & Wvg. Mills (P) Ltd., Ludhiana
- f. Deepak Spinners Ltd. Solan Baddi
- g. Shiva Fabricator (P) Ltd., Ludhiana
- h. Supreme Tex Mart Ltd., Ludhiana
- i. Yogendra Worsted Ltd., Ludhiana
- j. Shree Rajasthan Syntex Ltd, Dungarpur
- k. Banswara Syntex Ltd., Banswara
- l. Ganga Acrowools Ltd., Ludhiana
- m. Shital Fibres Ltd., Jalandhar
- n. Arisudana Industries Ltd., Ludhiana
- o. Sportking India Ltd., Ludhiana
- p. Texas Woollen Mills (P) Ltd., Ludhiana
- q. Jindal Cotex Ltd., Ludhiana
- r. Garg Acrylics Ltd., Ludhiana
- s. Indian Spinners' Association, Mumbai
- t. Ludhiana Spinners Association, Ludhiana

ix. The following importers or consumers of the product have filed the importer's questionnaire response in the prescribed format:

- a. Ganga Spinning and Weaving Mills Ltd.
- b. Banswara Syntex Ltd., Banswara
- c. Vanaik Spinning Mills Ltd.
- x. Submissions/ comments were filed by following parties during the course of the investigation :
 1. Delegation of the European Union to India and Bhutan
 2. Embassy of the Republic of Belarus, Embassy of Ukraine
 3. Embassy of Peru

4. Dralon GmbH, Germany
5. Jilin Qifeng Chemical Fiber Co. Ltd., Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. and China Jinshan Associated Trading Corporation from China PR
6. Sudamericana de Fibras S.A (Peru)
7. Open Joint-Stock Company Naftan Belarus
8. Indian Spinner Association, Punjab Spinners Association, Supreme NonWoven India Pvt. Ltd, Ganga Spinning and Weaving Mills Ltd, Ganga Acrowools Ltd, Banswara Syntex Ltd., and Vanaik Spinning Mills Ltd.
- x. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file, kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7). Submissions made by all interested parties have been taken into account in the present disclosure statement.
- xii. The Period of Investigation for the purpose of the present investigation has been considered from April 2016 – March 2017 (12 Months). The injury investigation period has been considered as the period April 2013 - March 2014, April 2014 - March 2015, April 2015 - March 2016 and the POI.
- xiii. Additional/supplementary information was sought from the applicant and other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the domestic industry and exporters/producers was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the investigation.
- xiv. The Non-Injurious Price (NIP) is based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules. It has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- xv. Information provided by the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) on transaction-wise basis for the past three years, and the period of investigation has been adopted for determination of volume and value of imports of product concerned in India.
- xvi. The Authority held an oral hearing on 12th March, 2018 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally in accordance to Rule 6(6) of AD Rules. All the interested parties who presented their views orally at the time of hearing were advised to file written submissions of the views expressed orally. The interested parties were also provided opportunity to offer rejoinder submissions to the submissions made by opposing interested parties.
- xvii. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this disclosure statement.
- xviii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xix. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded this disclosure statement on the basis of the facts available.
- xx. The Authority issued a disclosure statement under Rule 16 on 27th March, 2018 and provided an opportunity to give comments to the disclosure statement till 4th April, 2018.
- xxi. In this final findings, *** represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xxii. The exchange rate adopted by the Authority during the POI for the subject investigations is 1 US\$= Rs 67.95.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. The product under consideration for the purpose of present investigation is “Acrylic Fibre” (also referred to as “subject goods”).

B.1. Submissions made by Domestic industry

5. The domestic industry has submitted as follows with regard to product under consideration and like article:

- a. Acrylic Fibre is a long chain of synthetic polymer composed of at least 90% by weight of Acrylonitrile units (major raw material for production). The term Acrylic Fibre includes acrylic staple fibre, acrylic tow, and acrylic top, all of which are known as Acrylic Fibre in commercial parlance. The only difference between acrylic staple fibre and acrylic tow is the difference in length. In case of length more than 2 meters, it is known as tow and in case of cut lengths, it is known as staple fibre. All forms of acrylic fibre are within the scope of the product under consideration.
- b. Acrylic Fibre is lightweight, soft and warm with wool-like feel. It is very resilient and shows high resistance to acids and alkalis compared to other synthetics and natural fibres. Some varieties of acrylic fibre are used as less expensive alternative to cashmere wool due to the similar feeling of the materials. Acrylic Fibre is an economical substitute of wool. Acrylic fibre takes colour well, is washable, and is generally hypoallergenic.
- c. Acrylic Fibre is classified under chapter 55 of the Customs Tariff Act under the sub-heading 5501, 5503 and 5506 at 4-digit level. The product is covered under HS code 550130, 550330 and 550630 at six-digit levels and under 55013000 and 55033000 at eight-digit levels.
- d. Acrylic Fibre has application in day-to-day human life. Acrylic Fibre has variety of applications in apparel, household and industrial areas.
- e. Acrylic Fibre falls under Chapter 55 of the Customs Tariff Act under the category "Man Made Staple Fibres".
- f. Acrylic Fibres produced by the domestic industry should be treated as like article to the Acrylic Fibre imported from the subject countries in accordance with the Anti-dumping Rules.

B.2 Submissions made by other interested parties

6. The following submissions are made by other interested parties:
 - i. The PUC should not cover lower quality grades or second grades as they are inferior in technical characteristics and by definition do not meet the technical criteria to be classified as the product under consideration.
 - ii. It has been submitted by M/s Supreme Nonwoven that Homo Polymer Acrylic Fibre being a speciality fibre having superior properties should be exempted from the proposed anti-dumping duty. They have further stated that there is no producer of Homo Polymer Acrylic Fibre in India and that this product was excluded in previous antidumping investigations in notifications issued in August 2002 and 20th November 2008.

B.3. Examination by the Authority

7. The product under consideration is Acrylic Fibre. Acrylic Fibre is a long chain of synthetic polymer composed of at least 90% by weight of Acrylonitrile units (major raw material for production). The term Acrylic Fibre includes acrylic staple fibre, acrylic tow and acrylic top, all of which are known as Acrylic Fibre in commercial parlance. The only difference between acrylic staple fibre and acrylic tow is the difference in length. In case of length more than 2 meters, it is known as tow and in case of cut lengths, it is known as staple fibre. All forms of acrylic fibre are within the scope of the product under consideration.
8. Acrylic Fibre is lightweight, soft, and warm, with a wool-like feel. Its fibres are very resilient and shows high resistance to acids and alkalis compared to both other synthetics and natural fibres. Acrylic Fibre is an economical substitute of wool.
9. Acrylic Fibre is classified under chapter 55 of the Customs Tariff Act under the sub-heading 5501, 5503 and 5506 at 4-digit level. The product is covered under HS code 550130, 550330 and 550630. However, the customs classification is indicative only and in no way binding upon the product scope.
10. With regard to the issue of lower quality or second grades, the Authority notes that product cannot be excluded from the scope of the investigation merely on the quality grounds. Further, interested parties have not provided any evidence to demonstrate that these lower quality grades are not competing with the like article manufactured by the domestic industry. Therefore, Authority determines not to exclude these grades.
11. It is an admitted fact that the domestic industry does not manufacture Homopolymer Acrylic Fibre containing 100% Acrylonitrile. A letter from M/s Pasupati Acrylon Ltd. mentioning that they do not produce Homo Polymer Acrylic Staple Fibre too has been furnished. Therefore, the Authority determines to exclude "Homo Polymer Acrylic Fibre containing 100% Acrylonitrile" from the purview of the product under consideration.
12. After considering the information on record, the Authority holds that there is no known difference in the subject goods produced by the Indian industry and that exported from the subject countries. Subject goods produced by the Petitioners and that imported from the subject countries are comparable, in terms of product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Acrylic Fibre produced by the Domestic Industry

is technically and commercially substitutable to the imported Acrylic Fibre. The Authority holds that the product under consideration produced by the applicant domestic industry is like article to the subject product under consideration imported from the subject countries. However, the Authority determines to exclude “Homo Polymer Acrylic Fibre containing 100% Acrylonitrile” from the purview of the product under consideration.

C. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

13. Rule 2(b) of the AD rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term, ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers.”

C.1. Submissions made by the Domestic industry

14. Submissions made by the domestic industry in this regard are as follows:

- a. The Petition has been filed by M/s Indian Acrylics Ltd. and M/s Pasupati Acrylon Ltd.
- b. There is one other producer of the subject goods in India namely Vardhman Acrylics Ltd. Vardhman Acrylics Ltd. has imported significant volumes of subject goods from the Europe.
- c. Production of the Petitioners constitutes 78% of Indian production of the product under consideration.
- d. One of the Petitioners, Indian Acrylics Ltd., has imported the subject goods from Thailand under advance licenses against exports during the injury period.
- e. Petitioners are not related (either directly or indirectly) to any exporter or importer of product under consideration within the meaning of Rule 2(b).
- f. While Petitioners are not importers of the product under consideration from subject countries, Vardhman Acrylics Ltd. is a regular importer of product under consideration from the EU. Imports made by Vardhman Acrylics Ltd. are quite significant and are not for self-consumption. Petitioners have the standing whether Vardhman Acrylics is considered as an eligible or ineligible constituent of the domestic industry in view of its imports.

C.2. Submissions made by other interested parties

15. No submissions have been made by any of the interested parties in this regard.

C.3. Examination by the Authority

16. The present application has been filed by M/s Indian Acrylics Ltd. and M/s Pasupati Acrylon Ltd. as the domestic producers of the product under consideration.
17. The Authority notes that the Petitioners are two of the three main producers of the subject goods in India. Production of the Petitioners constitutes 78% of Indian production of the product under consideration.
18. In view of the above facts, the Authority holds that the Petitioners constitute Domestic Industry in terms of Rule 2(b) of the AD Rules and satisfy the standing requirement in terms of Rule 5(3) of the AD Rules.

D. CONFIDENTIALITY

D.1. Submissions made by the Domestic industry

19. Submissions made by the domestic industry in this regard are as follows:

- a. Though one of the producers from Peru has filed the questionnaire response, the Petitioners are unable to make any comments on the same in view of excessive confidentiality claimed by the Peruvian producer.

D.2. Submissions made by the other interested parties

20. Submissions made by other interested parties in this regard are as follows:

- a. Petitioners have not provided good cause statement as required under para 2.ii of Trade Notice No. 1/2009 in claiming confidentiality in respect of captive and export sales volume.
- b. Petitioners have claimed excessive confidentiality in respect of captive and exports sales volume without providing any basis for doing so.

c. While volumes of both exports and captive sales have been mentioned in the original Petition, they have been claimed as confidential in the updated Annexures. The domestic industry has not provided indexed figures also against these parameters, and has resorted to such misuse of confidentiality.

D.3. Examination by the Authority

21. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:

“7. Confidential information- (1) Notwithstanding anything contained in sub rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated Authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated Authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated Authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated Authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

22. Information provided by the domestic industry as well as other interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties.

E. MISCELLANEOUS ISSUES

E.1. Submissions made by the Domestic industry

23. Submissions made by the domestic industry in this regard are as follows:

a. Exporters from more than one country are dumping the subject goods in the Indian market. In terms of the provisions under Annexure II(iii) of the AD Rules, in case imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority should cumulatively assess the effect of such imports.

b. Export price from the subject countries significantly differs in terms of customer and time period and therefore it is a fit case where weighted average normal value cannot be compared with weighted average export price. The Authority is requested to consider weighted average normal value and compare with individual export price and in all those import transactions where the dumping margin is negative, the same may be excluded for determination of dumping margin.

c. Ukrainian imports should not be excluded from the scope of the investigation as it is well settled law that the injury analysis is undertaken considering the POI. The previous years are taken into account only to make a comparative analysis.

d. Duties have to be imposed as and when there are instances of dumping activities. None of the interested parties have established how the imposition of duties will impact the downstream users.

E.2. Submissions made by other interested parties

24. Submissions made by other interested parties in this regard are as follows:

a. Imports from Belarus were only 2.94% of the total imports to India during the POI as per the petition. It has been rounded off to 3% at certain places in the Petition. Investigation against Belarus is bad in law and should be terminated immediately.

b. Taiwan has been kept out of the scope of the present investigation. This is discriminatory and also frustrates the entire causal link analysis of injury. This situation also warrants termination of the present investigation in view of Rule 5(3).

c. The data with regard to capacity and ability to raise capital investments submitted by the Domestic Industry in their Petition differs from and is contrary to the data in their Annual Reports.

- d. Conditions of inter-se competition between the subject goods imported into India and the conditions of competition between the subject goods imported into India and the like domestic product are not the same. Therefore a cumulative assessment would not be appropriate.
- e. The requirement for the Authority to conduct cumulative assessment stands vitiated on the fact that Taiwan is not included in the scope of subject countries and share of Belarus was below 3% in total imports at the time of initiation. Such being the case, any cumulative assessment shall only lead to distorted conclusions and a country wise examination including Taiwan should be done in the present case.
- f. The end-user industry is already reeling under margin pressures, and the prices offered by the domestic industry are not competitive. In the interest of these end-users, the domestic industry should not recommend any anti-dumping duty as it will lead to the closure of a large number of small scale users of the product under consideration.
- g. Imports from the European Union should not be included in the cumulative assessment of the effect of imports since the landed value of the product under consideration from the EU is the highest, the market share of imports from the EU has declined in the POI, and volume of imports from the EU has declined in the POI.
- h. In almost every anti-dumping investigation initiated since 1996, anti-dumping duties have been recommended and levied on imports of Acrylic Fibre, some of which are still in place. Thus the domestic producers of Acrylic Fibre have had more than adequate protection from imports vide anti-dumping duties.
- i. In the context that a lot of specialty grades have been imported, a PCN wise comparison may be made to ensure fairness in determination of dumping and injury margin. The product here involves multiple grades and types and at the best a PCN analysis is appropriate.

E.3. Examination by the Authority

25. With regard to the various issues raised by the domestic industry and the other interested parties, the Authority notes as follows:

- a. With regard to the issue of imports from Belarus, the Authority notes that the actual volume of imports of the product under consideration from Belarus during the POI is more than 3% of the volume of all imports of the product under consideration. Therefore, there is no merit in the submission that the investigation against Belarus should be terminated in accordance with the AD Rules.
- b. With regard to the inclusion of Taiwan in the scope of investigations, the Authority notes that no arguments have been advanced or evidence produced to show that imports of the product under consideration from Taiwan are being dumped into India. Hence, there is no requirement to include Taiwan within the scope of this investigation.

F. MARKET ECONOMY TREATMENT (MET), NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

Normal Value

26. Under Section 9A(1)(c) of the Customs Tariff Act, 1975, as amended, the normal value in relation to an article means:-

- i. the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
- ii. When there are no sales of the like articles in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-
- a. Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
- b. the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

F.1. Submissions by the Domestic industry

27. Submissions made by the domestic industry in this regard are as follows:

a. One of the provisions of China PR's Accession Protocol has expired on 11th December, 2016. The Designated Authority may consider Chinese producers as producers operating in non-market economy conditions for the following reasons:

i. The investigation period proposed by the Petitioners in the present case is Jul 2016 to December 2016 (6 months). The injury investigation period has been proposed as the period 2013-14, 2014-15, 2015-16, April-June 2016, and the POI.

ii. The Chinese producers are required to be treated as non-market economy companies for the reasons that the costs and prices in China do not reasonably reflect the market forces.

iii. Chinese producers are required to be treated as non-market economy companies till such time the investigation period includes the period specified in China's Accession Protocol.

b. China PR had agreed to be considered as non-market economy upto 11th December 2016, as per the Accession Protocol. Technically, China PR held NME status during the proposed injury period as well as the POI proposed in the present case. Therefore, there should be no change in the status of China PR in this investigation.

c. Normal value in China PR, Belarus and Ukraine – Since they are non-market economies, the Authority should follow para 7 of Annexure I of the AD Rules.

d. None of the exporters from Ukraine and Belarus have responded to the Exporters Questionnaire. Thus the normal value of these countries should be determined in accordance with the written submissions filed by the Petitioners and as per best available information.

e. Petitioners have claimed determination of normal value in China PR, Belarus and Ukraine on the basis of regional prices of Acrylic Fibre prevailing in Asia (Far East) Region as per IHS Chemical reports for the proposed POI on CFR basis. The Authority may kindly apply ordinary course of trade test on these prices and ascertain that these prices are above full cost of production.

f. Petitioners have been able to get evidence of delivered basis prices prevailing in West Europe region as per IHS Chemical reports and have adopted these prices as the basis for the normal value for the proposed POI. The Authority may kindly apply ordinary course of trade test on these prices and ascertain that these prices are above full cost of production.

g. Petitioners have been able to get evidence of delivered basis prices prevailing in South America regions as per IHS Chemical reports and have adopted these prices as the basis for the normal value for the proposed POI. The Authority may kindly apply ordinary course of trade test on these prices and ascertain that these prices are above full cost of production.

h. All those import transactions where the dumping margin is negative should be excluded for determination of dumping margin.

F.2. Submissions made by other interested parties

28. Submissions made by the foreign producers/exporters/other interested parties with regard to normal value are as under:

a. The Authority should determine dumping margin by calculating the normal value and export price based on the Questionnaire response filed by the Exporters.

b. Ukraine should be treated as Market Economy Country. India has already recognised Ukraine as market economy in cold rolled coils investigation.

c. The export prices of Acrylic Fibre by OJSC Naftan are higher than the domestic selling prices of Acrylic Fibre in Belarus in the POI.

d. The Republic of Belarus is a state with market economy. The Govt. of India has recognized Belarus as a market economy during the visit of President Mukherjee to Belarus in 2015.

e. The exclusion of those transactions where the dumping margin is negative is a methodology known as zeroing which has been conclusively deemed to be inconsistent and in violation of the AD Agreement and the AD Rules.

F.3. Examination by the Authority

29. The following producers/exporters from the subject countries have filed exporter's questionnaire:

- a. Sudamericana de Fibras S.A (Producer) – Peru
- b. Jilin Qifeng Chemical Fiber Co. Ltd. (Producer/Exporter)– China PR
- c. Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. (Producer) – China PR
- d. China Jinshan Associated Trading Corporation(Exporter)– China PR
- e. Dralon GmbH, Germany (Producer/Exporter) – European Union
- f. Open Joint-Stock Company Naftan , Belarus

a) Examination of Market Economy Claims and Normal Value

30. Article 15 of China's Accession Protocol provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SC M Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

31. Article 15 implies that provisions of one of the sub-paragraph shall expire 15 years from date of China's Accession. The provisions of this sub-paragraph expired on 11th Dec., 2016. Since the factum of dumping causing injury to the domestic industry is established based on investigation period, the conditions prevalent during the investigation period alone is relevant, appropriate and necessary for the purpose of present investigation. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is April 2016 to March 2017. Since the subparagraph of Article 15 was in existence during the period of investigation, the Authority is entitled to use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

32. The Authority notes that in the past three years China PR has been treated as a non-market economy country in anti-dumping investigations by India and other WTO Members. China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the Rules.

33. As per Paragraph 8, Annexure I to the AD Rules as amended, the presumption of a non-market economy can be rebutted if the exporter(s) from China PR provides information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3) in Paragraph 8. The cooperating exporters/producers of the subject goods from People's

Republic of China are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Designated Authority to consider the following criteria as to whether:

- a. The decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values.
- b. The production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts.
- c. Such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms.
- d. The exchange rate conversions are carried out at the market rate.

Determination of Normal Value for producers and exporters in China PR

34. None of the exporters/producers from China PR have claimed market economy status. In the absence of any reliable price and cost details for the subject goods in any market economy third country, the normal value for China PR has been constructed considering optimum cost and consumption norms of the most efficient constituent of the domestic industry plus reasonable profit. The normal value so determined is provided in the Dumping Margin Table herein below.

Determination of Normal Value for producers and exporters in Belarus

35. Normal value for cooperating producer/exporter from Belarus is determined on the basis of information provided by the concerned producer/exporter as Belarus has been treated as market economy by the Government of India, which was conveyed to the Embassy of the Republic of Belarus vide letter no. 11/1/2013-FT(CIS) dated 10.06.2015 from the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India.

Open Joint-Stock Company Naftan (Belarus)

36. In view of questionnaire response from the producers/exporters in Belarus, normal value and dumping margin in case of responding producers and exporters has been determined on the basis of their questionnaire response.

37. From the Exporter Questionnaire response, the Authority notes that M/s Naftan, is a producer/exporter of the subject goods. As per information available in the exporter's questionnaire response, during the period of investigation, Naftan made *** MT domestic sales to unrelated customers. The ordinary course of trade (80:20) test conducted on the sales indicates that *** % of sales were profitable. The normal value of the subject goods in the POI therefore has been determined by taking average price of the profitable domestic sales in the subject country. No adjustments has been claimed from normal value by the company. The normal value is thus considered as *** USD/MT.

Determination of Normal Value for producers and exporters in Ukraine

38. The Authority notes that none of the producers/exporters from Ukraine have filed exporter questionnaire response. In view of non-cooperation from all the producer-exporters in Ukraine, the Authority has determined normal value on the basis of best available information in terms of Rule 6(8) and the same is indicated in the dumping margin table given below.

Determination of Normal Value for producer/exporters from European Union

Dralon GmbH, Germany (Exporter/Producer)

39. From the Exporter Questionnaire (EQ) response, the Authority notes that Dralon GmbH is a producer and exporter of the subject goods. Dralon has claimed normal value on the basis of sales made in the domestic market. As per information available in the EQ response, during the period of investigation Dralon made *** MT of domestic sales to unrelated customers. The ordinary course of trade (80:20) test conducted on the sales of Dralon indicates that ***% of the domestic sales are profitable. Therefore, normal value of the subject goods in the POI has been determined by taking average price of the profitable domestic sales in the subject country. Dralon has claimed adjustments on account of inland freight, packing cost, commission and credit cost. Authority has allowed the same after due verification and normal value is thus arrived as *** USD/MT.

Determination of Normal Value for producers and exporters in Peru

Sudamericana de Fibras S.A, Peru (Producer)

40. The Authority notes that Sudamericana de Fibras S.A from Peru has filed exporter questionnaire response.

41. From the Exporter Questionnaire (EQ) response, the Authority notes that Sudamericana de Fibras, Peru is a producer of the subject goods. Sudamericana de Fibras has claimed normal value on the basis of sales made in the domestic market. However, due to reasons given in subsequent paragraphs, normal value for Sudamericana de Fibras S.A has not been determined on the basis of the questionnaire response submitted by them but has been constructed on the basis of facts available.

Determination of Normal Value for Non-cooperating producers and exporters from European Union, Belarus and Peru

42. For the other producers/exporters of European Union, Belarus and Peru, normal value has been considered based on the facts available. Based on this the dumping margin is indicated in the dumping margin table.

b) Export Price

Determination of Export Price for producers/exporters from China PR

43. The Authority notes that the following producers/exporters from China PR have filed exporter questionnaire response:

- a. Jilin Qifeng Chemical Fiber Co. Ltd. (Producer/Exporter) – China PR
- b. Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. (Producer) – China PR
- c. Jinshan Associated Trading Corporation (Exporter) – China PR

44. In view of questionnaire response from the producers/exporters in China PR, export price in case of responding producers and exporters has been determined on the basis of their questionnaire response.

M/s Jilin Qifeng Chemical Fiber Co.Ltd., (“Jilin”) (Producer/Exporter), China PR

45. The Authority notes that Jilin has exported *** MT of the subject goods to India. All exports to India were made directly to unrelated Indian customers. Jilin had claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland freight and port handling charges. The Authority has made further adjustments for bank charges and credit cost to determine net export price at ex-factory level. The ex-factory export price for Jilin is determined as *** USD/MT.

M/s Sinopec Shanghai Petrochemical Co.,Ltd., (“Sinopec”) (Producer) and M/s Jinshan Associated Trading Corporation (Jinshan) (Exporter) China PR

46. The Authority notes that Sinopec has exported *** MT of the subject goods to India directly and through related trader Jinshan. The related trader has exported 316 MT through another trader Xinhe Trading HK Limited based in HongKong. Xinhe Trading HK Limited has not cooperated with the Authority. Accordingly, Authority determines not to accept the response filed by Sinopec and Jinshan. The Authority has accordingly determined export price on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) and the same is indicated in the dumping margin table given below.

Determination of Export Price for producers/exporters from Belarus

Open Joint-Stock Company Naftan (Belarus)

47. The Authority notes that Naftan has exported *** MT of the subject goods to India to unrelated customers in India. Naftan has not claimed any adjustment from the export price. All export sales to India were on FCA basis. Therefore, the Authority has made appropriate adjustments on account of inland freight, port handling charges, bank charges and credit cost to determine net export price at ex-factory level. The ex-factory export price is determined as *** USD/MT.

Determination of Export Price for producers/exporters from European Union

Dralon GmbH (Producer/ Exporter)

48. The Authority notes that Dralon GmbH has exported *** MT of the subject goods to unrelated customers in India. Dralon has claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland freight, port handling charges, commission and credit cost to determine net export price at ex-factory level, and the Authority has allowed the same after due verification. The ex-factory export price is determined as *** USD/MT.

Determination of Export Price for producers/exporters from Ukraine

49. The Authority notes that none of the producers/exporters from Ukraine have filed exporter questionnaire response. In view of non-cooperation from all the producer-exporters in Ukraine, the Authority has determined export price on the basis of best available information in terms of Rule 6(8) and the same is indicated in the dumping margin table given below.

Determination of Export Price for producers/exporters from Peru**Sudamericana de Fibras S.A, Peru (Producer)**

50. The Authority notes that Sudamericana de Fibras has sold *** MT of the subject goods to India. It is submitted by the producer that all exports to India were made directly to Indian customers. From the response filed by the producer, Authority notes that almost *** % of exports to India were made through Dubai based traders namely M/s. Trans Galactic Trading FZ and M/s. Lanis Fibras Limited. Further, from the sample documents provided by the company, it is noted that the export price reported by the producer is not matching with the values in export invoices. Therefore, the Authority decides to not accept the response of Sudamericana de Fibras. Accordingly, the export price for Sudamericana de Fibras has been determined on the basis of facts available.

Determination of Export Price for Non-cooperating producers and exporters from China PR, European Union, Belarus and Peru

51. For the other producers/exporters of China PR, European Union, Belarus and Peru, the export value has been considered based on the facts available. Based on this the dumping margin is indicated in the dumping margin table.

F.4. Calculation of Dumping Margin

52. Comparing the aforesaid normal values and export prices as determined, the dumping margin proposed to be determined for the subject countries during POI are as follows:

Dumping Margin Table

Country	Producer	Exporter	Normal Value	Ex-factory Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	Dumping Margin
			US\$/MT	US\$/MT	US\$/MT	%	Range
China PR	M/s Jilin Qifeng Chemical Fiber Co.Ltd	M/s Jilin Qifeng Chemical Fiber Co.Ltd	***	***	***	***	0-10
China PR	All Others	All Others	***	***	***	***	0-10
Belarus	Open Joint-Stock Company Naftan	Open Joint-Stock Company Naftan	***	***	***	***	30-40
Belarus	All Others	All Others	***	***	***	***	65-75
European Union	Dralon GmbH	Dralon GmbH	***	***	***	***	10-20
European Union	All Others	All Others	***	***	***	***	30-40
Ukraine	All	All	***	***	***	***	0-10
Peru	All	All	***	***	***	***	20-30

53. It is seen that the dumping margins are more than the de-minimis limits prescribed under the Rules in respect of exports made from each of the cooperating producers/exporters and non-cooperative producers/ exporters from subject countries.

G. DETERMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

54. The Petitioners have alleged that the dumped imports from the subject countries are causing material injury to the domestic like product in India. Having determined that the goods are entering from the subject countries at dumped prices, the Authority proceeds to examine the degree and extent of injury, if any, suffered by the domestic industry.

55. Rule 11 of the Rules read with Annexure – II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

G.1. Submissions made by the Domestic Industry

56. Submissions made by the domestic industry in this regard are as follows:

- i. Landed price of subject goods has remained below the cost of sales as well as the selling price. Imports are suppressing/depressing the domestic prices.
- ii. Imports are resulting in significant price underselling as evidenced by the difference between the non-injurious price and landed price of imports.
- iii. Performance of the domestic industry has deteriorated in terms of production, capacity utilization, sales, inventories, profits, return on investments, cash flow, and market share.
- iv. The deterioration in performance of the domestic industry is more prominent in the POI on quarterly basis.
- v. Domestic industry has been prevented from utilizing its capacities to the fullest extent on account of continued dumped imports in the market from existing and fresh sources.
- vi. Market share of the domestic industry declined drastically over the injury period whereas that of subject countries has increased. Market share of Indian industry as a whole has also declined despite having sufficient capacity to cater to the demand.
- vii. Domestic industry is not in a position to make any fresh investments.
- viii. Anti-dumping duty is urgently required to be imposed on subject countries in order to prevent further deterioration of performance of the domestic industry.
- ix. The capacity utilization of any industry is seen for the production as a whole, since at the stage of production, the domestic and export production cannot be segregated.
- x. Employment and wages are not truly reflective factors of the injury being suffered by the domestic industry.
- xi. With regard to return on capital employed, domestic industry has claimed volume injury in the present case.
- xii. The dumping margin is positive and therefore the fact that the import prices declined due to raw material price decline is irrelevant. The domestic industry suffered adverse volume effect due to price undercutting and resultant increase in imports. As a direct consequence, the production, capacity utilization, market share, sales volumes declined and inventories increased.
- xiii. The ROI of the domestic industry over the injury period have been quite low. Further, the average ROI of the domestic industry since its inception have been quite low. The domestic industry has never paid dividend to the shareholders and is facing quite low credit ratings.
- xiv. Price undercutting should be determined only considering injurious import transactions. Petitioner's concern is not against non-injurious imports. Reference is made to the Hon'ble CESTAT's decision in Kothari Sugars & Chemicals Ltd. vs. DA. Reference is also made to WTO panel report in EC – Tube or Pipe Fittings.

G.2. Submissions made by the foreign producers/exporters/other interested parties

57. Submissions made by the foreign producers/exporters/other interested parties in this regard are as follows:

- i. The domestic industry's claims of injury need extra scrutiny by the Authority as the facts show a robust situation.
- ii. Demand has not fallen per se. The exporters are capable of supplying specialty product given the divergent needs of the Indian users and the domestic industry's inability to cater to the demand for specialty grades should not be seen as an adverse implication for market share.
- iii. Profitability of domestic industry with regard to domestic sales has not declined rather has substantially increased. In fact, in 2015-16 and 2016-17, the domestic industry has made super profits. Similarly, cash profits, profit before interest and tax, and return on capital have substantially increased in the injury period.
- iv. Production and capacity utilization have significantly increased in the injury period. In fact, capacity utilization has settled at a high of 89% in the POI.
- v. Domestic sales have declined because domestic industry is diverting its production for export sales as can be seen from an increase in export sales value.
- vi. Decline in domestic industry's domestic sales volume can be explained by decline in total demand for the subject goods in India.
- vii. Annual Report of Pasupati Acrylon Ltd. itself states that it has taken a conscious decision to increase thrust on exports.

- viii. Petitioners' market share in India has declined due to increased focus on exports and decline in demand in domestic market.
- ix. Market share of Other Domestic Producer – Vardhman Acrylics Ltd, has remained more or less the same in spite of absolute increase in import volume from the subject countries. This shows that the Domestic Industry has not been as efficient and competitive as the other domestic producer.
- x. Market share of imports from the EU has decline in the POI in comparison to the base year.
- xi. The increase in Domestic Industry's inventory is due to increase in export sales. Increase in inventory must be assessed as a percentage of total sales volume.
- xii. Increase in import volume as a proportion of both production and consumption has been not more than 10% throughout the injury period, which cannot be considered significant at all.
- xiii. Share of subject imports as a proportion of overall imports is not a factor for determination of volume effect and hence of injury.
- xiv. Volume of imports from the EU has declined in the POI.
- xv. Petitioners' calculation of landed value is erroneous as customs duty and cess have been added to the CIF value instead of the assessable value, thereby resulting in a lower landed value.
- xvi. Though the landed value is the same in both the Original Petition and the revised Annexures for the years 2013-14, 2014-15, and 2015-16, the price undercutting range in the revised Annexures has been shown as 0-30%. Such a dramatic increase needs explanation. Further, the range of undercutting of 0-30% is too wide in comparison to an acceptable range of 5-10 points.
- xvii. Domestic industry has not reduced its domestic selling prices to the extent of the decline in raw material costs, which the exporters have done, thereby resulting in landed prices being lower than the domestic selling prices.
- xviii. Impact of imports from Taiwan is not segregated and it cannot be said that any alleged impact on various injury parameters is on account of imports from subject countries.
- xix. Landed value of imports from the European Union is the highest.
- xx. The Petitioner – Indian Acrylics Ltd. has cited demonetization as having affected growth in its Annual Report 2016-17.
- xxi. Decline in domestic sales volume in 2016 is due to warm winter and increase in preference of lower-priced leather jackets.
- xxii. The economic parameters such as salary and wages, employees, return on capital employed, and profit/(loss) demonstrate that the Petitioners have in fact seen a positive growth during the POI and hence cannot state that it is suffering injury.
- xxiii. The Appellate body in the European Communities – Anti-Dumping Duties On Imports Of Cotton-Type Bed Linen From India WT/DS141/AB/R dated March 1, 2001 held that the zeroing methodology is inconsistent with Article 2.4 and Article 2.4.2 of the AD Agreement
- xxiv. Hon'ble Tribunal's order in the case of Kothari Sugars & Chemicals Limited versus Designated Authority (2005 (187) ELT 185 Tri Del) that has been relied upon by the Petitioners cannot be considered in the present factual matrix. The Hon'ble Tribunal's order was based on the fact that the data from EU was incomplete and the imports were preventing a price increase
- xxv. It is reiterated that the performance of the petitioner especially profitability clearly establishes neither direct nor indirect link between the two i.e., domestic industry's performance and importation of subject goods. It is also pertinent to mention here that the profitability of the petitioners were at their lowest when the imports from the subject countries were at its lowest (i.e., during the base year) but the same increased significantly over the injury period including POI despite alleged increase in alleged dumped imports from subject countries. This clearly proves that the import from the subject countries has not impacted on the profitability of the petitioners' or its commercial performance.
- xxvi. The decline in volume parameters, when the DI could admittedly maintain its prices at robust margin levels cannot be presumed to have been caused by alleged dumped imports.
- xxvii. It can be seen that all the parameters that existed in Playing Cards case are almost similar as the parameters existing in Acrylic Fibre case. Thus, in view of the above, the Anti-Dumping Duty should not to be continued and present investigation should be terminated on the same grounds.

xxviii. The decline in volume parameters when the domestic industry could admittedly maintain its prices at robust margin levels cannot be presumed to have been caused by alleged dumped imports.

xxix. An objective examination of injury necessitates examination of overall position of the domestic industry including the price parameters which would show that there is no injury as envisaged in the AD Rules. If a holistic view of the case is taken then there is no case of injury demonstrated by the domestic industry.

G.3. Examination by the Authority

a) Cumulative Assessment

58. Annexure II (iii) of the AD Rules provides that in case imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigation, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that: -

a) the margin of dumping established in relation to the imports from each country/ territory is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent of the imports of the like article or where the export of the individual countries is less than three percent, the imports cumulatively accounts for more than seven percent of the imports of like article, and;

b) Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

59. In the present case, the margin of dumping from each of the subject countries have been found to be more than the de minimis limit prescribed; the volume of dumped imports from each of the subject countries is more than the limits prescribed; and the exports from the subject countries directly compete inter se and with the like goods offered by the domestic industry in the Indian market. Cumulative assessment of the effects of the dumped imports is appropriate in the light of the conditions of competition between the imported products and the conditions of competition between the imported products and the like domestic product. The Authority, therefore, considers it appropriate to cumulatively assess the effect of dumped imports from the subject countries.

b) Examination of Injury Parameters

60. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties. The Authority has examined the submissions made by the domestic industry and other interested parties with regard to the injury in accordance with the Antidumping Rules.

i. Assessment of Demand and Market Share

61. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian Producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Demand	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Sales of Domestic Industry	MT	52,739	41,655	48,200	37,749
Sales of Other Producers	MT	20,616	20,620	20,585	18,333
Imports - Subject Countries	MT	12,596	14,215	16,270	17,951
Import - Other Countries	MT	19,523	17,257	18,493	13,445
Total Demand	MT	1,05,203	93,746	1,03,548	87,479
Market Share	%				
Domestic industry	%	50	44	47	43
Other Producers	%	20	22	20	21
Subject countries	%	12	15	16	21
Other Countries	%	18	18	18	15
Total	%	100	100	100	100

62. The Authority notes that the demand for the product under consideration has decreased in the POI. Demand has declined from 2013-14 to 2014-15, before increasing in 2015-16. However, there is decline in demand in the POI as compared to 2015-16 and also earlier years. The market share of the domestic industry has declined from 50% in 2013-14 to 44% in 2014-15. It then increased slightly to 47% in 2015-16 before again declining to 43% in the POI.

63. The market share of the other domestic producer has more or less remained stable during the injury period.

64. Market share of the subject countries on the other hand has increased from 12% in the base year to 15% in 2014-15 to 16% in 2015-16 and then to 21% in the POI.

Volume and Price Effect of the dumped imports on the Domestic industry

ii. Volume Effect: Import Volume and share of subject countries

65. With regard to volume of the dumped imports, the Authority has examined whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume of imports of the subject goods from the subject countries have been analyzed as under:

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Import Volumes					
China	MT	23	1,529	2,737	2,989
Belarus	MT	2,185	2,613	1,322	1,023
European Union	MT	10,388	10,073	12,034	9,357
Ukraine	MT	-	-	-	2,195
Peru	MT	-	-	177	2,387
Subject Countries	MT	12,596	14,215	16,270	17,951
Countries attracting ADD	MT	11,274	12,683	13,670	10,656
Other Countries	MT	7,979	4,573	4,823	2,790
Total	MT	31,848	31,471	34,763	31,397
Market Share in Imports					
China PR	%	0.07	4.86	7.87	9.52
Belarus	%	6.86	8.30	3.80	3.26
European Union	%	32.62	32.01	34.62	29.80
Ukraine	%				6.99
Peru	%			0.51	7.60
Subject Countries	%	39.55	45.17	46.80	57.18
Countries attracting ADD		35.40	40.30	39.32	33.94
Other Countries	%	25.05	14.53	13.87	8.88
Total	%	100.00	100.00	100.00	100.00
Demand	MT	1,05,203	93,746	1,03,548	87,479
Indian Production	MT	88,211	85,220	1,01,386	90,869
Subject Imports in relation to					
Demand	%	12	15	16	21
Indian Production	%	14	17	16	20

66. The Authority notes that the volume of dumped imports of the product under consideration have increased in absolute terms as well as in relation to consumption and production in the country, throughout the injury period, except during 2015-16 when it marginally declined in relation to the production as compared to previous year.

67. Share of imports from the subject countries as a whole in relation to the total imports into India has increased to 57.18% in the POI from 39.55% in the base year.

iii. Price Effect of dumped imports and impact on the domestic industry

68. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or

whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in normal course.

69. Accordingly, the impact on the prices of the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject countries has been examined with reference to price undercutting, price suppression/depression and price underselling, if any. For the purpose of this analysis the cost of production, Net Sales Realization (NSR) and the Non-injurious Price (NIP) of the Domestic industry have been compared with the landed price of imports from subject countries.

Price Undercutting

70. Price undercutting has been determined by comparing the landed price of imports from the subject countries with the net sales realisation of the domestic industry in India.

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Net Sales Realization	Rs/MT	***	***	***	***
Subject Countries as a whole					
Landed Price	Rs/MT	1,64,370	1,71,432	1,33,021	1,15,383
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Price undercutting %	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	Negative	Negative	0-10	10-15
BELARUS					
Landed Price	Rs/MT	1,81,152	1,81,901	1,34,812	1,08,167
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Price undercutting %	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	Negative	Negative	0-5	15-20
CHINA PR					
Landed Price	Rs/MT	2,36,374	1,67,059	1,30,136	1,18,984
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Price undercutting %	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	Negative	0-5	0-5	0-10
EUROPEAN UNION					
Landed Price	Rs/MT	1,60,682	1,69,380	1,33,618	1,18,619
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Price undercutting %	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	0-5	Negative	0-5	0-10
UKRAINE					
Landed Price	Rs/MT	-	-	-	1,17,680
Price undercutting	Rs/MT	-	-	-	***
Price undercutting %	%	-	-	-	***
Price undercutting	Range	-	-	-	5-15
PERU					
Landed Price	Rs/MT	-	-	1,23,702	99,173
Price undercutting	Rs/MT	-	-	***	***
Price undercutting %	%	-	-	***	***
Price undercutting	Range	-	-	0-10	20-30

71. It is seen from the table above that the landed price of imports from the subject countries are undercutting the domestic selling prices in the POI.

Price Suppression / Depression

72. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices, the Authority notes the changes in the costs and prices over the injury period. The position is shown as per the table below:

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Indexed</i>		100	104	76	73

Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Indexed</i>		100	103	84	81
Landed Price from subject countries	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Indexed</i>		100	104	81	70

73. The cost of sales has declined by 27% in the POI as compared to base year whereas the Petitioners have decreased the selling price only by 19% in the POI. So, imports have had no suppressing effect on the domestic selling price. The landed price of imports from subject countries has been above the cost of sales of the domestic industry throughout the injury investigation period and also during the POI.

Price underselling

74. The Authority has also examined price underselling suffered by the domestic industry on account of dumped imports from subject countries. It is noted that there has been price underselling only from Belarus and Peru during the POI on account of dumped imports. There has been no price underselling from China PR, EU and Ukraine during the POI as can be seen in the table below:

Particulars	Unit	China PR	Belarus	EU	Ukraine	Peru
Non-Injurious Price	Rs/MT	***	***	***	***	***
Landed price of imports in POI	Rs/MT	1,18,984	1,08,167	1,18,619	1,17,680	99,173
Price Underselling	Rs/MT	***	***	***	***	***
Price Underselling	%	***	***	***	***	***
Price Underselling	Range%	Negative	0-10	Negative	Negative	0-20

G.4. Examination of economic parameters relating to the domestic industry:

75. Annexure II to the AD Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of like products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of like products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth and ability to raise capital investments.

76. Accordingly, various economic parameters of the domestic industry are analyzed herein below:

a) Capacity, Production and Capacity Utilization & Sales

77. The Authority has considered capacity, production, capacity utilization and sales volume of the domestic industry over the injury period and notes as follows:

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Capacity	MT	81,600	81,600	81,600	81,600
Production	MT	67,783	64,425	80,706	72,536
Capacity Utilisation	%	83	79	99	89
Domestic Sales	MT	52,739	41,655	48,200	37,749
Demand	MT	1,05,203	93,746	1,03,548	87,479

78. It is noted from the table above that:

- The domestic industry has maintained the same level of capacity over the entire injury period and POI.
- While production declined in 2014-15, it increased significantly in 2015-16, before declining again in the POI. Capacity utilization increased to 99% in 2015-16 before settling at 89% in the POI.

iii. The volume of domestic sales decreased in 2014-15 before increasing in 2015-16 and again decreasing in the POI.

b) Market Share of Domestic industry in demand

79. The effects of the dumped imports on the market share of the domestic industry have been examined as below. It is noted that barring slight increase during 2015-16, the market share of the domestic industry has decreased throughout. The market share of the other domestic producer, Vardhman Acrylics Ltd., however has remained at more or less the same level.

Market Share	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Domestic Industry	%	50	44	47	43
Other Producer	%	20	22	20	21
Subject Countries	%	12	15	16	21
Other Countries (including countries attracting ADD)	%	18	18	18	15
Total	%	100	100	100	100

c) Stock/inventories

80. The Authority further notes that the average inventory levels of the domestic industry has shown increasing trend. However, the inventory levels cannot be considered in isolation and hence the Authority deems it necessary to examine the same with the volume of total sales.

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Average Inventory	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	117	143	172
Total Sales	MT	68,762	62,834	81,314	70,589
Inventory as a proportion of total sales	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	%	3%-5%	3%-5%	3%-5%	3%-5%

81. Inventory as a proportion of total sales has increased only by a small percentage during the POI. The average inventory level is equivalent to approximately half a month's production only.

d) Profits, Cash Profits and Return on Capital Employed

82. Performance of the domestic industry was examined in respect of profits, cash profits and return on capital employed.

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Cost of Domestic Sales	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Indexed</i>		100	104	76	73
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Indexed</i>		100	103	84	81
Profit / Loss	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	87	322	320
Profit / Loss	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	69	294	229
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	68	217	170
Profit before Interest & Tax	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	73	212	165
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
<i>Trend</i>		<i>100</i>	<i>79</i>	<i>239</i>	<i>176</i>

83. It is noted from the table above that:

- Profits/ MT has increased substantially in the POI and the preceding year (2015-16).
- Cash profits have improved considerably during 2015-16 before registering a slight decline in the POI. However, even after the slight decline, cash profits in the POI are much above the cash profit in the base year.
- Return on capital employed has improved significantly in the injury period.
- Return on capital employed has been well above the standard 22% allowed by the Authority while determining the NIP throughout the injury investigation period including POI.
- Return on capital employed during the POI was as high as in the range of 50%-60%.

e) Employment and Wages

84. It is seen from the table below that the number of employees has witnessed marginal increase in 2015-16 and POI. Salaries and wages paid by the domestic industry have however increased in greater proportion.

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI-A
Employment	Nos	***	***	***	***
<i>Trend</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>103</i>	<i>106</i>
Salary and Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>		<i>100</i>	<i>108</i>	<i>116</i>	<i>146</i>

f) Growth

85. Examination of growth parameters of the domestic industry during the injury period is shown below.

Growth	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Production	%	-	-4.95	25.27	-10.12
Sales	%	-	-21.02	15.71	-21.68
Capacity Utilization	%	-	-4.82	25.32	-10.10
Profit/Loss per unit	%	-	-12.67	268.19	-0.46
Return on Capital Employed	%	-	-21	160	-63
Market Share - DI	%	-			

g) Level of Dumping and Dumping Margin

86. The dumping margin in respect of each of the subject countries is not only more than de-minimis but also significant.

h) Factors affecting domestic prices

87. The selling prices of the domestic industry has not been affected by dumped imports from the subject countries because there is no price suppression. The domestic industry is earning healthy profits and return on capital employed. The selling price of the domestic industry during POI was significantly more than the NIP determined by the Authority.

i) Ability to raise fresh Investment

88. The Authority notes that the domestic industry is earning healthy profits and healthy return on capital employed, therefore it has the ability to raise fresh investments.

G.5. Magnitude of Injury And Injury Margin

89. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry when compared with the landed value of the exports from the subject country shows the position as under :

Country	Producer	Exporter	NIP US\$ per MT	Landed Value US\$ per MT	Injury Margin US\$ per MT	Injury Margin INR per MT	Injury Margin %
			US\$/MT	US\$/MT	US\$/MT	%	Range
China PR	M/s Jilin Qifeng Chemical Fiber Co.Ltd	M/s Jilin Qifeng Chemical Fiber Co.Ltd	***	***	***	***	(10)-0
China PR	All Others	All Others	***	***	***	***	(10)-0
Belarus	Open Joint-Stock Company Naftan	Open Joint-Stock Company Naftan	***	***	***	***	0-10
Belarus	All Others	All Others	***	***	***	***	15-25
European Union	Dralon GmbH	Dralon GmbH	***	***	***	***	(15)-0
European Union	All Others	All Others	***	***	***	***	(5)-0
Ukraine	All	All	***	***	***	***	(10)-0
Peru	All	All	***	***	***	***	5-15

H. POST DISCLOSURE STATEMENT SUBMISSIONS BY THE INTERESTED PARTIES

90. The post disclosure submissions have been received from the interested parties. Majority of the issues raised therein have already been raised earlier during the investigation and also addressed appropriately. Additional submissions have been analysed as under:

H.1. Submissions by the domestic industry

91. The Domestic Industry has made the following submissions:

- i. Homo polymer is also acrylic fibre and is not a separate product and should not be excluded from the PUC. There has been no exclusion in the scope of the PUC by the Authority in several investigations conducted in the past.
- ii. The POI in the present investigation is within the year 2016, which is well before the expiry of China's Accession Protocol. In any case, the provisions of Article 15(a)(i) of the Accession Protocol are still applicable and must be considered for determination of normal value for China.
- iii. The Authority has constructed the normal value based on best available information and have considered cost of production of the domestic industry for the same. However, the earlier submitted evidence of price of Acrylic Fibre prevailing in Asia (Far East) Region as per IHS Chemical report has not been considered. There is no reasoning in the disclosure statement as to why such information cannot be accepted and the hierarchy laid down under the law should not be followed.
- iv. The import volume has increased despite a decline in demand. This fact is sufficient to hold that the domestic industry has suffered injury.
- v. The volume of subject imports constitutes significant share of imports into India and such share, as a whole, to the total imports into India has increased to 57.18% in the POI from 39.55% in the base year.
- vi. The prior submission that price undercutting should be determined considering only those transactions whose landed price of imports is below the selling price of the domestic industry, though noted by the Authority, has not been examined.
- vii. The cost of sales increased till 2014-15 but declined thereafter. The selling price of the domestic industry also followed the same trend but the landed price of the subject goods remained below the cost of sales as well as the selling price.
- viii. In determination of price effect, the AD rules have an "OR" as a requirement and not "AND" between suppression/depression and price undercutting.
- ix. The domestic industry's production has improved till 2015-16 and declined thereafter in the POI. Sales have declined significantly over the injury period and the decline is much more than the decline in demand. Capacity utilization has declined as compared to the year preceding the POI.

- x. The Authority is requested to correlate various parameters relating to the domestic industry, while concluding adverse volume effect in the present case. Imports have not followed the trend of demand. Even when demand declined, imports increased.
- xi. Inventories have increased both in absolute terms and in proportion to domestic sales. The legal requirement is whether performance of the domestic industry deteriorated in respect of inventories. There was no reason for the domestic industry to increase its inventories when its production and sales were falling.
- xii. The domestic industry has been forced to suspend production and suffered heavily due to decline of production and sales. It would also be seen that there is a direct correlation between decline in production and increase in inventories.
- xiii. The domestic industry's market share has declined drastically over the injury period whereas that of the subject countries has increased. Market share of Indian industry as a whole has also declined despite having sufficient capacity to cater to the demand.
- xiv. The domestic industry's profitability, cash profit and return on investment has improved. Thus, the effect of dumping is not visible on these parameters. The domestic industry withheld price declines partially at the time of reduction in raw material prices in view of its long adverse performance with regard to profits.
- xv. The continued/renewed dumping/long history of dumping from various sources has not given the Petitioners a single chance to recover from the ill effects of such continuous dumping and pay dividends to its shareholders even once.
- xvi. The wages paid and number of employees has increased in the injury period. These are not solely dependent on the performance of the subject goods, and are governed by overall operations of the company and the economy. They may not reflect the adverse impact of dumping.
- xvii. The domestic industry is not in a position to make any fresh investments as it is facing dumping of imports from various countries.
- xviii. The average import price from subject countries is much lower than the non-injurious price of the domestic industry showing significant injury margin.
- xix. The imports of the PUC from other countries are negligible, both in volume and value, and imports from Thailand are already attracting duty. Almost 57% of imports are from subject countries.
- xx. There is a decline in demand of the subject product. However, imports from subject countries have increased in the injury period including POI, thus, causing material injury to the domestic industry in a situation of declining demand.
- xxi. In past investigation such as viscose staple fibre, front axle beam; wherein the demand for the PUC had declined; the Authority held that the increase in imports in a situation of decline in demand established that dumping has caused injury to the domestic industry.
- xxii. Detailed breakup of NIP has to be disclosed by the Authority.
- xxiii. The NIP considered by the Authority has been quite low thereby resulting in an unduly low injury margin.
- xxiv. The Authority may disclose the non-confidential version of the verification report of the exporters/producers from the subject countries to offer meaningful comments on the dumping margin calculated.
- xxv. The disclosure statement gives an impression that the following have been considered as facts, whereas these are parameters: trends in import volume; price effect; cumulative assessment of injury. Essential facts under consideration with regard to injury to the domestic industry have not been disclosed in the disclosure statement.
- xxvi. The form of anti-dumping duty should be fixed quantum of anti-dumping duty.
- xxvii. The anti-dumping duty should be imposed in terms of US\$ in the final determination. Rupee has depreciated significantly and therefore, the definitive duties may kindly be expressed in US\$.

H.2. Submissions by other interested parties

92. The following submissions have been made by producers/exporters/importers/other interested parties:

- i. The downstream industry is forced to import several types of speciality acrylic fibres on account of non-availability/non-manufacturing of the same by any domestic producer. The need and requirement of specific types of Acrylic Fibre for the production of downstream goods of specific quality/characteristic is not governed by the import price but on account of specific speciality acrylic fibre.
- ii. These speciality fibres are required for qualities like anti-piling, soft and lustrous look etc. which is not possible to achieve by using acrylic fibre produced by Indian producers. Hence, the import of these speciality fibres should be kept out of the scope of PUC for the purpose of instant investigation.

- iii. There are differences between the first quality grades and the lower quality grades. These cannot be considered as “like articles” because they are different with respect to technical and commercial substitutability, product specifications, functions and end-uses, end-user requirement and pricing. The Authority may exclude Second Grade from the scope of the PUC.
- iv. The normal value of OJSC Naftan should be determined on the basis of information provided in the questionnaire because Belarus was recognized by the Government of India as a country with a market economy.
- v. OJSC Naftan disagrees with the dumping margins calculated by the Authority. According to the information sent by OJSC Naftan in the questionnaire, the dumping margin is negative. Thus, the investigation against acrylic fibre produced by OJSC Naftan should be terminated.
- vi. The Authority is requested to take into account the submissions made by Sudamericana de Fibras S.A in order to calculate the export price rather than merely construct it. Accordingly, Sudamericana may also be granted an individual margin of dumping and injury.
- vii. A negative injury margin has been calculated for China PR, European Union and Ukraine. This indicates that only 19% of the subject imports are below non-injurious price. There is no cause for injury to be caused by those low-priced imports, which are above the NIP.
- viii. While the point-to-point analysis of the trend of imports shows that the imports have increased, the trend of increased imports is not established during the entire injury period (for FY 2015-2016 there is dip in the imports into India).
- ix. Given the fact that there is no injury margin for imports originating from China PR, European Union and Ukraine (comprising more than 75% of total imports from subject countries) the volume and price effect do not establish a causal link between injury to the domestic industry and the low-priced imports from subject countries.
- x. There is an inherent contradiction in the manner in which the conclusion on underselling has been arrived. The disclosure statement states that there is underselling in the prices of PUC, however the table shows that there is no underselling from more than 75% of the imports in India from subject countries.
- xi. There is a pattern of fixed increase and decrease in capacity utilization of the domestic industry.
- xii. Since major financial parameters such as profits, cash flows and return on capital employed have substantially improved, the economic indicators do not provide a substantive evidence as to existence of injury to the domestic industry.
- xiii. The Disclosure Statement does not provide any analysis on the impact of such duties on the users / importers. If duty is levied on Acrylic Fibre then the cost of spinning companies for acrylic yarn will increase.
- xiv. The impact of duty will have to be absorbed by the ailing spinning industry since the weavers and knitters (end users of acrylic yarns) do not have alternative sources available from sources outside India.
- xv. The import volume of acrylic fibre produced by Belarusian companies has decreased and does not cause any injury to the domestic industry, or threat thereof.
- xvi. The imposition of anti-dumping duty on imports of the PUC will harm the users and lead to the closure of a large number of small end-users of the PUC.
- xvii. The production, capacity utilization and sales has moved in accordance with the market trend over the injury period.
- xviii. There is contraction in demand for the PUC in the POI as compared to 2015-16. The market share of the domestic industry has followed a similar trend. The domestic industry's market share is also required to be seen in the light of inter-se fibre competition and need for speciality fibre by the user industry.
- xix. While determining volume effect, the Authority must note that the increase in subject imports is largely on account of necessity for speciality fibre for production of speciality yarn in order to remain relevant in the increasingly competitive market due to free availability of imported material on account of various FTAs with the countries like Thailand, Bangladesh, Sri-Lanka etc.
- xx. A simple comparison of NSR with landed price in India will not give a true account as regard to price-undercutting as the Petitioners' domestic selling prices are significantly higher than the NIP.
- xxi. The domestic industry has resorted to premium pricing in domestic market to subsidise their export sales and such examination of price under-cutting with significantly higher price of the domestic industry would result in a skewed analysis and distorted picture.
- xxii. There is neither price suppression/depression nor price underselling. The imports have shown no impact on the pricing of the petitioners' performance in this respect.

- xxiii. The domestic industry's sales performance is required to be analysed keeping in view the contraction of demand and inter-se fibre competition.
- xxiv. The decline in market share is also required to be seen in light of contraction of demand, inter-se fibre competition and need for importation of speciality fibre which is other-wise not produced domestically.
- xxv. Only 20% of the total imports in the POI was from Belarus and Peru and the rest were from EU, Ukraine and China PR. In such a scenario, any decision to still slap anti-dumping duties on Belarus and Peru based on the positive IM on paper would be illogical and irrational given the fact that the domestic industry did not suffer any material injury.
- xxvi. The domestic producers in India lag in production technology and are incapable of producing speciality fibres. As a result, the user industry is forced to import the same for the purpose of staying relevant in the market in the background of stiff competition due to various FTAs
- xxvii. There is a direct conflict of interest between the Indian producers of Acrylic Fibre and user industry in India. The domestic industry shares a dual relationship with the user industry i.e., that of client and competitor. The domestic industry is charging higher prices for subject goods from the user industry not only to earn higher profits but also to gain an economic edge over user industry in the downstream market as well, which certainly qualifies as both restrictive as well as anti-competitive practices.
- xxviii. Cognizance should have been taken with regard to imports from Taiwan which were much higher than the imports from Belarus. The share of imports from Taiwan stood at about 5% in total imports and the price from Taiwan was lower than the price of the subject goods from subject countries.
- xxix. Without prejudice, should the domestic industry still claim injury on account of imports from subject countries, they need to first establish why imports from Taiwan were not causing any injury though they were above de-minimis levels and also at lower prices comparable to subject countries.
- xxx. With regard to the inclusion of Taiwan in the scope of investigations, the Authority notes that no arguments have been advanced or evidence produced to show that imports of the product under consideration from Taiwan are being dumped into India. Hence, there is no requirement to include Taiwan within the scope of this investigation.
- xxxi. Sudamericana de Fibras S.A has complied with the confidentiality requirements as per AD Rules and trade notices. Therefore, the Petitioner's excessive confidentiality claims made with respect to Sudamericana should be disregarded.

H.3. Examination by the Authority

93. The examination by the Authority for the issues raised above and considered relevant is as under:
- i. The product under consideration is Acrylic Fibre. It is a long chain of synthetic polymer composed of at least 90% by weight of Acrylonitrile units (major raw material for production). The term Acrylic Fibre includes acrylic staple fibre, acrylic tow and acrylic top, all of which are known as Acrylic Fibre in commercial parlance. The only difference between Acrylic staple fibre and Acrylic tow is the difference in length. In case of length more than 2 meters, it is known as tow and in case of cut lengths, it is known as staple fibre.
 - ii. Acrylic Fibre is lightweight, soft, and warm, with a wool-like feel. Its fibres are very resilient and shows high resistance to acids and alkalies compared to both natural and other synthetics fibres. Acrylic Fibre is an economical substitute of wool.
 - iii. Acrylic Fibre is classified under chapter 55 of the Customs Tariff Act under the sub-heading 5501, 5503 and 5506 at 4-digit level. The product is covered under HS code 550130, 550330 and 550630. However, the customs classification is indicative only and in no way binding upon the product scope.
 - iv. With regard to the issue of lower quality or second grades, the Authority notes that product cannot be excluded from the scope of the investigation merely on the quality grounds. Further, interested parties have not provided any evidence to demonstrate that these lower quality grades are not competing with the like article manufactured by the domestic industry. Therefore, Authority determines not to exclude these grades.
 - v. It is an admitted fact that the domestic industry does not manufacture Homopolymer Acrylic Fibre containing 100% Acrylonitrile. A letter from M/s Pasupati Acrylon Ltd. mentioning that they do not produce Homo Polymer Acrylic Staple Fibre too has been furnished. Therefore, the Authority determines that the scope of the product under consideration is all forms of Acrylic Fibre except Homo Polymer Acrylic Fibre containing 100% Acrylonitrile.
 - vi. After considering the information on record, the Authority intends to hold that there is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry in India and that exported from the subject countries. Subject goods produced by the Petitioners and that imported from the subject countries are comparable, in terms

of product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Acrylic Fibre produced by the Domestic Industry is technically and commercially substitutable to the imported Acrylic Fibre. The Authority proposes to hold that the product under consideration produced by the applicant domestic industry is like article to the subject product under consideration imported from the subject countries. However, the Authority holds that “Homo Polymer Acrylic Fibre containing 100% Acrylonitrile” should be excluded from the purview of the product under consideration.

- vii. No evidence has been adduced by any of the interested parties to show that the domestic producers lag in production technology and are incapable of producing speciality fibres. Therefore, it is not shown that possible injury to the domestic industry could have been caused by developments in technology.
- viii. With regard to the claim concerning market economy status, Authority notes that none of the exporters/producers from China PR has claimed market economy status. Normal value for China PR has been constructed considering optimum cost and consumption norms of the most efficient constituent of the domestic industry plus reasonable profit in terms of the provisions under the Anti-Dumping Rules and the consistent practice of the Authority.
- ix. With regard to the submission made by OJSC Naftan regarding their dumping margin determination, the Authority notes that the dumping margin for OJSC Naftan has been determined in accordance with the Anti-Dumping Rules.
- x. With regard to the submission made by Sudamericana de Fibras S.A for determining individual dumping and injury margin for them, the Authority notes that it is not possible for the Authority to determine individual dumping and injury margin because of non-participation of all the parties involved in export chain to India.
- xi. With regard to the inclusion of Taiwan in the scope of investigation, the Authority notes that no arguments have been advanced or evidence produced to show that imports of the product under consideration from Taiwan are being dumped into India. Hence, there is no requirement to include Taiwan within the scope of this investigation.
- xii. As regards existence of injury due to increase in imports and decline in demand, Authority observes that examination of injury involves examination of all factors relevant under Annexure II of the Anti-dumping Rules.
- xiii. With regard to the submission that price undercutting should be determined by considering only transactions whose landed price of imports is below the selling price of the domestic industry, Authority observes that it is the established practice of the Designated Authority that price undercutting analysis is undertaken taking into account all the import transactions.
- xiv. As regards the claim that NIP determined by the Authority should be disclosed, Authority notes that detailed calculation of NIP was disclosed to the domestic industry along with the disclosure statement.
- xv. As regards the claim that verification report of the exporters/producers should be disclosed, Authority notes that such verification reports contain confidential information of the exporters and such report is not disclosed by the Authority in any anti-dumping investigation.
- xvi. With regard to confidentiality of information, Authority has examined the confidentiality claims of the interested parties. The Authority has considered the claims of confidentiality made by the petitioners and the opposing interested parties and on being satisfied about the same, the Authority has allowed the claim on confidentiality. The Authority had made available to all interested parties the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection, upon request as per Rule 6(7).
- xvii. As regards the claim that disclosure statement should disclose conclusion reached by the Authority on injury parameters, Authority notes that disclosure statement is issued in accordance with Rule 16 of the Anti-dumping rules by which it has informed all interested parties of the essential facts under consideration which would form the basis of the final decision.
- xviii. Authority has noted the submissions made by the domestic industry and other interested parties with regard to injury in accordance with Anti-dumping Rules. The Authority notes that profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry have substantially improved over the injury period. Return on capital employed during the POI was as high as in the range of 50%-60%. The selling price of the domestic industry for subject goods during POI was significantly more than the NIP determined by the Authority. The imports have had no suppressing effect on the domestic selling price.
- xix. The Authority further notes that even though there has been an increase in the volume of dumped imports from the subject countries in absolute terms and in relation to production and consumption in India, the landed price

of subject goods during POI from China PR, EU and Ukraine has been above the NIP determined by the Authority for the domestic industry. Imports from these three subject countries account for approximately 81% of the total imports of subject goods from all the subject countries taken together. Therefore, approximately 81% of the imports from all the subject countries taken together cannot be said to be causing injury to the domestic industry.

- xx. On a holistic analysis of all the injury parameters, it can be concluded that the domestic industry is not suffering material injury as contemplated under the Anti-Dumping Rules.

G.6. Conclusions on Injury

94. Considering various parameters relating to material injury provided under the Anti-Dumping Rules, the Authority concludes as follows:

- a. There has been an increase in the volume of dumped imports from the subject countries in absolute terms and in relation to production and consumption in India. Dumping margin from the subject countries is also positive and significant. However, landed price of subject goods during POI from China PR, EU and Ukraine has been above the NIP determined by the Authority for the domestic industry. Imports of subject goods from these three subject countries account for approximately 81% of the total imports from all the subject countries taken together. Therefore, approximately 81% of the imports from all the subject countries taken together cannot be said to be causing injury to the domestic industry. The imports from subject countries have also not caused any kind of price suppression for the domestic industry.
- b. The landed price of imports from subject countries has been above the cost of sales of the domestic industry throughout the injury investigation period and also during the POI.
- c. While capacity of the domestic industry has remained at the same level during the injury period, the other parameters like production, capacity utilization and market share of the domestic industry have followed a fixed pattern of decrease and increase in alternate years.
- d. Profits, cash profits and return on capital employed have substantially improved over the injury period.
- e. Return on capital employed during the POI was as high as in the range of 50%-60%.
- f. The selling price of the domestic industry for subject goods during POI was significantly more than the NIP determined by the Authority.

95. Based on the above, the Authority concludes that the domestic industry is not suffering material injury during the POI in terms of the relevant provisions under the Anti-Dumping Rules.

H. CAUSAL LINK AND OTHER FACTORS

96. As the Authority has concluded that the domestic industry is not suffering any material injury during the POI, the Authority is not undertaking causal link and non-attribution analysis.

I. RECOMMENDATION

97. Having examined the contentions of various interested parties and on the basis of above facts, circumstances and analysis, the Authority concludes that the domestic industry is not suffering material injury in terms of the provisions enshrined under the Anti-Dumping Rules. In view of the above, the Authority does not consider it appropriate to recommend levy of anti-dumping duty on the imports of subject goods from subject countries and hereby terminates this investigation in accordance with Rule 14(b) of the Anti-Dumping Rules.

J. FURTHER PROCEDURE

98. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this Final Findings Notification shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy.